राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 07 फरवरी 2026 वर्ष-9,अंक-15 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

महिला की मर्जी के बिना

मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती अदालत

● सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत,कहा-महिला की प्रजनन स्वायत्तता सर्वोपरि

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में महिला के प्रजनन संबंधी अधिकारों और उसकी स्वायत्तता को सर्वोपरि माना है। कोर्ट ने शुक्रवार को एक 18 वर्षीय युवती को 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। साथ ही हाई कोर्ट ने सुझाव दिया था कि युवती को बच्चे को जन्म देना चाहिए और बाद में उसे गोद दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा- अदालत किसी भी महिला को उसकी गर्भावस्था पूरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, यदि वह ऐसा नहीं करना चाहती है। युवती ने 17 साल की उम्र में गर्भधारण किया था, और अब वह 18 साल 4 महीने की है। यह गर्भ एक मित्र के साथ संबंध के कारण ठहरा था। कोर्ट ने माना कि इस गर्भावस्था को जारी रखना युवती के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद दर्दनाक होगा। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि गर्भपात की प्रक्रिया से युवती की जान को कोई गंभीर खतरा नहीं है। युवती के वकील ने तर्क दिया कि अवैध बच्चे को जन्म देने से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचेगा। कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि अपीलकर्ता के अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है, भले ही निर्णय लेने में देरी हुई हो।

● यहां मुख्य मुद्दा यह है कि लड़की गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती- दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि यहां मुख्य मुद्दा यह है कि लड़की गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती। अदालत ने कहा- यह प्रश्न नहीं है कि संबंध सहमति से था या नहीं। वास्तविकता यह है कि बच्चा अवैध है और मां बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मां की प्रजनन स्वायत्तता को महत्व दिया जाना चाहिए। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून के तहत 20 सप्ताह तक महिला स्वयं गर्भपात का निर्णय ले सकती है। 20 से 24 सप्ताह के बीच मेडिकल बोर्ड की राय जरूरी होती है। 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति केवल अदालत दे सकती है। अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए 30 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी और याचिकाकर्ता से इसके लिए लिखित सहमति देने का निर्देश दिया।

टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज आज से

● मुंबई में यूएसए के साथ भारत खेलेगा पहला मैच

नई दिल्ली (एजेंसी)। टी-20 वर्ल्ड कप कल शनिवार से शुरू हो रहा है। इनमें 20 टीमों के 300 प्लेयर्स हिस्सा लेंगे। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हो रहे इस टूर्नामेंट में 4 अलग-अलग ग्रुप में मैच होंगे। टीमों में अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें सबसे युवा हैं, दोनों की औसत आयु 25-25 साल है। जबकि न्यूजीलैंड और यूएसए की टीमें सबसे उम्रदराज हैं। इनमें औसत आयु 31-31 साल है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चर्चा ग्रुप ऑफ डेथ को लेकर है। इस बार यह टैग ग्रुप-डी को मिला है। जिसमें पिछली बार की फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका के साथ 2021 की रनर-अप न्यूजीलैंड और पिछली सेमीफाइनलिस्ट अफगानिस्तान शामिल हैं। ग्रुप-ए में भारत और पाकिस्तान जैसी राइवल टीमों के अलावा ग्रुप-सी में 2-2 बार की चैंपियन इंग्लैंड और वेस्टइंडीज भी आमने-सामने हैं। ग्रुप-ए में डिफेंडिंग चैंपियन भारत और पाकिस्तान जैसी राइवल टीमें हैं। जबकि नीदरलैंड और नामिबिया भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं। कागजों पर भारत और पाकिस्तान को मजबूत दावेदार माना जा रहा है, लेकिन पिछले टी-20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया था।

नेपाल से सटे यूपी के जिलों के लिए आया नया नियम

● अब बगैर पैन कार्ड नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री

लखनऊ (एजेंसी)। भारत और नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों में संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने अब इन जिलों में संपत्ति रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले फॉर्म-60 भरकर रजिस्ट्री करने की सुविधा थी जो अब खत्म कर दी गई है। यह फैसला मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धन के निवेश और सीमा पार से जुड़े संदिग्ध लेन-देन को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। यूपी की महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें विभागीय ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण सॉफ्टवेयर में खरीदार और विक्रेता दोनों पक्षों के पैन कार्ड की अनिवार्य प्रविष्टि और सत्यापन की व्यवस्था लागू की गई है। यह नया नियम विशेष रूप से नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में लागू किया गया है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में अक्सर बेनामी या फर्जी नामों से संपत्ति खरीदने की शिकायतें आती रही हैं।

विकसित भारत को अपना सपना बनाएं

● पीएम बोले-एक साल में हर विदेशी चीज स्वदेशी से बदलें

परीक्षा पे चर्चा-पीएम ने बच्चों को असम के गमछे पहनाए

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडीशन में देशभर से आए बच्चों से मुलाकात की। दिल्ली स्थित पीएम आवास पर मोदी ने पहले बच्चों को असम के गमछे पहनाए और फिर उनके सवालों के जवाब दिए। पहले एपिसोड में मोदी ने बच्चों को विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी चीजें अपनाने की सलाह दी। साथ ही, बच्चों से कहा कि वो 25 साल में विकसित भारत बनाने को अपना सपना बनाएं। पीएम बोले- जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब आप लोग 39-40 साल के होंगे। आपको अभी से विकसित भारत को अपना सपना बनाना चाहिए। भगत सिंह आजादी का सपना दिल में रखकर फांसी पर झूल गए। जो आजादी से 25 साल पहले, 30 साल पहले बलिदान किए गए, उसी से आजादी मिली। अपना सपना बनाएं कि विकसित भारत के लिए मुझे क्या करना है।

● देश की अमर कहानियों पर गेम बनाओ -गोवा के श्रीजीत गाडगिल ने सवाल किया, मेरा गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मगर पेरेंट्स नहीं समझते। मैं क्या करूं। पीएम ने जवाब दिया- भारत देश कहानियों से भरा हुआ है। आप खुद के गेम बनाओ। पंचतंत्र की कहानियों पर गेम बनाओ। अभिमन्यु की कहानी पर गेम बनाओ और अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर लॉन्च करो। धीरे-धीरे देखोगे कि कितने लोग तुम्हारे गेम्स खेल रहे हैं।

● मार्क्स-मार्क्स की बीमारी से बचो -एक स्टूडेंट के सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा- पता नहीं ये मार्क्स- मार्क्स की बीमारी कैसे फैल गई है। आप लोगों को पिछले साल के टॉप 1 से 10 तक के नाम याद हैं क्या ये उपलब्धि तो कुछ देर के लिए होती है। हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है।

पंजाब में एएपी नेता की गोली मारकर हत्या

● जालंधर में गुरुद्वारे के बाहर हमला,6 गोलियां मारीं

जालंधर (एजेंसी)। पंजाब के जालंधर में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेता लक्की ओबरॉय की 6 फरवरी की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे 53 साल के थे। स्कूटी पर आए हमलावरों ने उन्हें 6 गोलियां मारीं। 5 सीने में और एक गोली सिर पर लगी। लक्की ओबेरॉय मॉडल टाउन इलाके में गुरुद्वारे में माथा टेकने आए थे। जैसे ही वे गुरुद्वारे से निकलकर अपनी थार गाड़ी में बैठने लगे तो बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां चलते हुए का सीसीटीवी फुटेज भी समाने आया है। परिजन गंभीर हालत में उन्हें मॉडल टाउन के प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार को विश्वास नहीं हुआ तो वे उन्हें शहर के श्रीराम अस्पताल लेकर गए। यहां भी उन्हें मृत बताया गया। एडीसीपी जयंत पुरी ने बताया कि पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस को उनकी टारगेट किलिंग का शक है। ओबेरॉय आम आदमी पार्टी से जालंधर कैंट में वार्ड-35 के हलका इंचार्ज थे। उनका 5 दिन पहले ही बर्थडे था। पुलिस जांच में सामने आया कि गैंगस्टर शेरू ग्रुप ने 25 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमकी दी थी। लक्की ओबेरॉय के साथ प्रधानगी को लेकर झगड़ा चल रहा था।

पाक की शिया मस्जिद में जोरदार धमाका

● आत्मघाती हमले में 70 लोगों की मौत,12 से ज्यादा घायल

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के शहजाद टाउन इलाके में स्थित शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती हमला हुआ। द टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में 70 लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस और बचाव सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और पॉलीक्लिनिक अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। धमाके के बाद इस्लामाबाद के पुलिस प्रमुख ने पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अधिकारियों को आशंका है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। इससे पहले भी 11 नवंबर 2025 को न्यायालय के बाहर आत्मघाती धमाका हुआ था।

स्वदेशी स्टील्थ वाला एचएएल का 'मास्टर प्लान' तैयार

आईएएफ को धड़ाधड़ देगा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की बड़ी सरकारी एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि अगर वह एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं भी बनी तो भी जब इसके असली प्रोडक्शन का टाइम आएगा तो योगदान जरूर देगी। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी रिपोर्ट हैं कि देश की पहली पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट के शुरुआती स्टेज से एचएएल को बाहर कर दिया गया है। अब एचएएल के सीएमडी ने कई मीडिया हाउस को खुद बताया है कि देश के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर उनके क्या मास्टर प्लान हैं।

2035 तक एएमसीए प्रोजेक्ट में शामिल होने का इंतजार

डीके सुनील के मुताबिक अभी एएमसीए प्रोटोटाइप स्टेज में है और हमें उम्मीद है कि बड़ा ऑर्डर (इंडियन एयर फोर्स को सप्लाई के लिए) 2035 के आसपास दिया जाएगा। हम उस समय इसके लिए दावेदार होंगे। अगले दशक में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ में एएमसीएको नहीं रखा गया है। मतलब, देश के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर एचएएल मास्टर प्लान बनाकर आगे बढ़ने की सोच चुका है, जिसमें डिजाइन और डेवलपमेंट के पचड़े में वह अभी नहीं पड़ेगी, सीधे प्रोडक्शन में शामिल होने का इंतजार करेगी। एचएएल सीएमडी के अनुसार एएमसीए 10 साल का प्रोजेक्ट है और अगर वह मान भी लें कि पांच प्रोटोटाइप को तैयार करने के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता।

● मौजूदा प्रोजेक्ट पर फोक करना चाहती है एचएएल- दरअसल, एचएएल अभी उन प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहती है, जिस पर पहले से ही वह काम कर रही है। इसके तहत उसके पास तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ट्रेनर, सिविलियन इस्तेमाल वाले हेलीकॉप्टर शामिल हैं। उसके पास इनके ऑर्डर पहले से ही भरे पड़े हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को उममीद है कि उसके पास जल्द ही तेजस का भी ऑर्डर आने वाला है। संभावना है कि 4.5वीं पीढ़ी के इस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान जो एडवांस वर्जन है, 2030-31 तक उत्पादन का ऑर्डर मिल सकता है। फिलहाल एचएएल का पूरा फोकस तेजस पर ही है, जिसकी कई डेडलाइन मिस हो चुकी है। कंपनी ने कहा है कि उसके पास पांच फाइटर जेट पूरी तरह से वायु सेना में शामिल होने के लिए तैयार हैं और इंडियन एयर फोर्स से इसको लेकर बातचीत चल रही है।

● जनता ने खारिज कर दिया तो अदालत आ गए!

चीफ जस्टिस ने प्रशांत किशोर की जनसुराज को खूब सुनाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बिहार चुनाव रद्द करने की मांग की थी। जनसुराज की दलील थी कि चुनाव से पहले मुफ्त वाली योजनाओं के ऐलान से ऐसा नतीजा आया है।

इसलिए बिहार चुनाव के नतीजों को अवैध घोषित कर नए सिरे से इलेक्शन कराए चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने तीखा रुख अपनाया है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यदि आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है तो आप राहत पाने के लिए अदालत में आ गए। यह तो सही चीज नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज की अर्जी को खारिज कर दिया और सुनवाई से ही इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी।

● जनसुराज ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर उठाए सवाल- जनसुराज ने अपनी अर्जी में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर सवाल उठाए थे। इसके तहत नीतिश कुमार सरकार ने चुनाव से ऐन पहले ऐलान किया था कि हर परिवार की एक महिला के खाते में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस रकम से वे अपना स्वरोजगार शुरू कर सकती है। यही नहीं आंकलन के बाद मदद के तौर पर इन महिलाओं को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त रकम भी दी जाएगी।

एअर इंडिया के 191, इंडिगो के 148 विमानों में बार-बार खराबी

सरकार ने संसद में माना-754 प्लेन की जांच में यह बात सामने आई

नई दिल्ली (एजेंसी)। हवाई यात्रा की सुरक्षा सवालों में है। जनवरी 2025 से देश की छह प्रमुख एयरलाइंस के कुल 754 विमानों की तकनीकी जांच की गई। इनमें से 377 विमानों में बार-बार आने वाली खराबियों की पहचान हुई। यानी एक ही खराबी बार-बार सामने आई, भले ही उसे पहले ठीक कर दिया गया था। एअर इंडिया ग्रुप के 267 विमानों में से 191 (72 फीसदी) में बार-बार तकनीकी खराबी पाई गई। इसके बाद इंडिगो का नंबर था। इसके 405 विमानों की जांच की गई। उनमें से 148 में इस साल 3 फरवरी तक रिपीटेटिव डिफेक्ट (एक ही खराबी बार-बार) पाई गई। लोकसभा में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि एजेंसी ने पिछले साल सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर जांच की। इस दौरान 3890 सर्विलांस इंस्पेक्शन, 56 ऑडिट, 492 रैंप चेक और 84 विदेशी विमानों की जांच की गई। 874 स्पॉट चेक और 550 नाइट सर्विलांस भी किए गए। एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने सरकारी डेटा जारी के बाद कहा, हमने बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हुए अपने पूरे फ्लीट में चेक किए हैं, इसलिए संख्या ज्यादा है।

● स्पाइसजेट के 16 विमानों में गड़बड़ी- इसके अलावा, स्पाइसजेट के 43 विमानों में से 16 में बार-बार गड़बड़ी होने का पता चला तथा आंकड़ों के अनुसार, विश्लेषण किये गए 32 विमानों में से कुल 14 अकासा एअर विमानों में बार-बार होने वाली गड़बड़ी की बात सामने आई। इसी दौरान, विमानन सुरक्षा नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भी 3,890 निगरानी निरीक्षण किए। मंत्री ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पिछले तीन वर्षों में उड़ानों में तकनीकी गड़बड़ी के मामलों की संख्या में कमी आई है और गत वर्ष ऐसी केवल 353 घटनाएं हुईं। मोहोल ने बताया कि वर्ष 2024 में तकनीकी गड़बड़ी के कुल 421 मामले सामने आए, जो इसके पिछले वर्ष की 448 घटनाओं से कम है। डीजीसीए के पास सभी विमान और हवाई अड्डा संचालकों के लिए नियमों के अनुपालन की निगरानी होगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

डराने लगी है ऑनलाइन गेमिंग की लत एवं आभासी दुनिया

सरकार और समाज की भूमिका भी इस संकट में कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके सामाजिक प्रभावों पर पर्याप्त नियंत्रण और निगरानी का अभाव है। कई गेम्स में हिंसा, आक्रामकता और जोखिम भरे व्यवहार को सामान्य और रोमांचक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों के लिए आयु-उपयुक्त सामग्री, समय-सीमा और चेतावनी संकेतों को सख्ती से लागू करना अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। सरकार को चाहिए कि वह ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल कंटेंट के लिए स्पष्ट और कठोर नियामक ढाँचा विकसित करे, जिसमें बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि हो।

(लेखक - ललित गर्ग-)

ऑनलाइन गेमिंग की लत एवं आभासी दुनिया कितनी भयावह एवं घातक हो सकती है, इसकी एक ही दिन में दो अलग-अलग जगह घटी घटनाओं ने न केवल झकझोरा है, बल्कि यह हमारे समय, हमारी सामाजिक संरचना और हमारी सामूहिक असावधानी पर लगा हुआ एक गहरा प्रश्नचिह्न बना है। धीरे-धीरे किशोरवय को अपने चपेट में लेने वाली यह प्रवृत्ति कितनी हृदयविदारक हो सकती है, उसका उदाहरण बुधवार को घटी ये दो भयावह घटनाएं हैं। एक हृदयविदारक घटना में गाजियाबाद की तीन अल्पवयस्क बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 12, 14 और 16 साल की तीन सुकोमल बहनें असमय काल-कवलित हो गईं। ऑनलाइन कोरियन गेम की दीवानी बहनें कोरिया में जाकर बसने और वहीं नया जीवन शुरू करने का सपना देखती थीं। घर वालों ने जब उनकी ऑनलाइन सनक से परेशान होकर उनसे मोबाइल छीन लिए, तो वे तनाव व अवसाद में घिर गई। फिर तीनों बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसी ही घटना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी घटी जहां एक पंद्रह वर्षीय किशोर ने ऑनलाइन गेम के अपने एक विदेशी साथी के बिछुड़ने के गम में घर में आत्महत्या कर ली। किशोर दसवीं का छात्र था। इन घटनाओं ने समाज को स्तब्ध ही नहीं किया, बल्कि भीतर तक गहरा घाव दिया है। यह कोई आकस्मिक या अलग-थलग घटना नहीं है। इससे पहले झाबुआ, भोपाल और देश के अन्य हिस्सों में सामने आई ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि आभासी दुनिया किस तरह वास्तविक जीवन पर हावी होती जा रही है और हम अनजाने में एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां संवेदनाएं, संवाद और जीवन-मूल्य स्क्रीन के पीछे दम तोड़ते जा रहे हैं।

ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में अपराध नहीं है, न ही तकनीक शत्रु है, लेकिन जब यह बच्चों और किशोरों के लिए लत बन जाए, तो यह एक धीमा जहर बन जाती है। यह जहर चुपचाप बच्चों के मस्तिष्क में प्रवेश करता है, उनकी सोच, उनकी भावनात्मक संरचना और उनके निर्णय लेने की क्षमता को विकृत करता है। गेमिंग की दुनिया बच्चों को तात्कालिक रोमांच, आभासी जीत और काल्पनिक पहचान देती है, लेकिन धीरे-धीरे वही दुनिया उन्हें वास्तविक जीवन से काट देती है। परिवार, मित्र, पढ़ाई, प्रकृति, खेल और संवाद-सब कुछ पीछे छूटने लगता है। गाजियाबाद की तीनों बहनों का यह कदम इसी कटाव का चरम और भयावह परिणाम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अत्यधिक ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के मस्तिष्क में आवेग नियंत्रण को कमजोर करती है। जोखिम का आकलन करने की क्षमता घटती है और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ती है। हार, असफलता या गेम से वंचित किए जाने की स्थिति में अवसाद, क्रोध और निराशा गहराने लगती है। कई बार बच्चे आत्महत्या जैसे चरम कदम को भी एक 'गेम ओवर' की तरह देखने लगते हैं। यह सोच अपने आप में अत्यंत खतरनाक है। आत्महत्या की प्रवृत्ति का बढ़ना केवल मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक चुनौती है, जो हमारी परवरिश, हमारी प्राथमिकताओं और हमारी नीतियों पर सवाल उठाती है।

आज के परिवारों में माता-पिता की व्यस्तता, एकल परिवारों की बढ़ती संख्या और संवाद की कमी ने बच्चों को अकेलेपन की ओर धकेला है। स्मार्टफोन कई घरों में बच्चों की चुप्पी खरीदने का सबसे आसान साधन बन गया है। रोता बच्चा हो, जिद करता बच्चा हो या समय न देने की मजबूरी-मोबाइल फोन एक त्वरित समाधान बन चुका है। लेकिन यही समाधान आगे चलकर सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि बच्चा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मार्गदर्शन, स्नेह और समय चाहता है। जब यह सब उसे स्क्रीन से मिलने लगता है, तो परिवार की भूमिका स्वतः कमजोर हो जाती है। यह भी एक कठोर सत्य है कि कई माता-पिता स्वयं डिजिटल लत के शिकार हैं। ऐसे में बच्चों को रोकने का नैतिक और व्यवहारिक अधिकार भी कमजोर पड़ जाता है। हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वे मोबाइल कम चलाएं, जबकि हमारे अपने हाथों में हर समय फोन रहता है। यह दोहरा व्यवहार बच्चों के मन में भ्रम और विद्रोह दोनों पैदा करता है। इसलिए समस्या का समाधान केवल बच्चों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि पूरे पारिवारिक वातावरण में संतुलन लाने से जुड़ा है।

सरकार और समाज की भूमिका भी इस संकट में कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके सामाजिक प्रभावों पर पर्याप्त नियंत्रण और निगरानी का अभाव है। कई गेम्स में हिंसा, आक्रामकता और जोखिम भरे व्यवहार को सामान्य और रोमांचक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों के लिए आयु-उपयुक्त सामग्री, समय-सीमा और चेतावनी संकेतों को सख्ती से लागू करना अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। सरकार को चाहिए कि वह ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल कंटेंट के लिए स्पष्ट और कठोर नियामक ढाँचा विकसित करे, जिसमें बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि हो। विद्यालयों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रह सकती। डिजिटल साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन-कौशल को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए, न कि तकनीक के गुलाम कैसे बना जाए। शिक्षकों को भी बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों, अकेलेपन, चिड़चिड़ेपन और अचानक गिरते शैक्षणिक प्रदर्शन जैसे संकेतों को गंभीरता से लेना होगा।

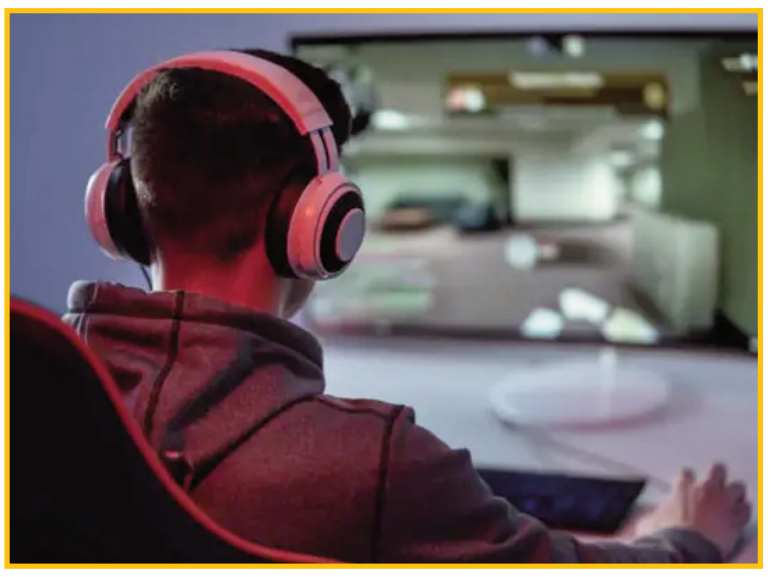

मनोवैज्ञानिक सहायता को लेकर समाज में जो झिझक और संकोच है, उसे भी तोड़ना होगा। मानसिक स्वास्थ्य को कमजोरी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। यदि किसी बच्चे में अवसाद, अत्यधिक चुप्पी, आक्रामकता या आत्मघाती विचारों के संकेत दिखें, तो समय रहते विशेषज्ञ की मदद लेना अत्यंत आवश्यक है। देर करना कई बार अपूरणीय क्षति में बदल जाता है। निस्संदेह, ये आत्मघात की घटनाएं, ऑनलाइन गतिविधियों के अतिरेक से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को लेकर गंभीर सवालों को जन्म देती हैं। निश्चित रूप से आत्मघात की ये घटनाएं हमारे नीति-नियंताओं और अभिभावकों को आसन्न संकट के प्रति सचेत करती हैं। दरअसल,ये दुखद घटनाएं एक घातक प्रवृत्ति को ही उजागर करती हैं कि गेमिंग और डिजिटल संपर्क लाखों युवाओं को आभासी समुदाय और मनोरंजन तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भावनात्मक कमजोरियों,सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति न होने जैसी समस्याओं को भी जन्म दे सकते हैं। हालांकि, वहीं दूसरी ओर समाज विज्ञानी इस बात पर भी बल देते हैं कि केवल गेमिंग या ऑनलाइन मित्रता ही आत्महत्या का कारण नहीं बन सकती हैं। निस्संदेह, आत्महत्या एक जटिल और बहुआयामी घटना है। लेकिन समस्याग्रस्त डिजिटल जुड़ाव, विशेष रूप से जब यह ऑफलाइन जीवन से अलगाव, बाधित शिक्षा और तीव्र भावनात्मक तनाव के साथ होता है तो संवेदनशील युवा मन में परेशानी को और बढ़ा सकता है।

गाजियाबाद की यह घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमने बच्चों के लिए कैसी दुनिया बनाई है। क्या हमने उन्हें संवाद दिया, या केवल उपकरण थमा दिए? क्या हमने उन्हें संस्कार दिए, या केवल सुविधाएं? क्या हमने उन्हें सुनने का समय दिया, या केवल आदेश? यह आत्ममंथन केवल पीड़ित परिवारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे समाज को अपने भीतर झांककर देखना होगा।

यह घटना एक चेतावनी है, एक टर्निंग पॉइंट है। यदि अब भी हमने इसे एक सामान्य समाचार की तरह भुला दिया, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। समाज को, सरकार को और प्रत्येक परिवार को मिलकर कड़े और संवेदनशील कदम उठाने होंगे। तकनीक को नकारना समाधान नहीं है, लेकिन उसे बिना नियंत्रण स्वीकार करना भी आत्मघाती है। संतुलन, संवाद और सहभागिता ही बच्चों की सुरक्षा का वास्तविक आधार हैं। गाजियाबाद की तीनों बहनों हो या कूल्लु के किशोर की असमय मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि अगर हमने अभी नहीं संभला, तो यह इलेक्ट्रॉनिक खतरा हमारे घरों, हमारे भविष्य और हमारी संवेदनाओं को निगलता चला जाएगा। यह समय है जागने का, सोचने का और ठोस कदम उठाने का-क्योंकि यह सवाल केवल तकनीक का नहीं, बल्कि जीवन का है।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

खनन पर हो मनन

सत्ताधीशों की इच्छा शक्ति की कमी और प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही से खनन माफिया के हौसल बुलंद हैं। कहीं न कहीं नागरिकों की उदासीनता भी इसके मूल में हैं। पंजाब के रोपड़ जिले की शिवालिक पहाड़ियों में हो रही तबाही उस भयावह स्थिति को दर्शाती है, जिसका खमियाजा आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। वजह साफ है कि अंधाधुंध खनन से शिवालिक पहाड़ियों के पारिस्थितिकीय तंत्र को भारी क्षति पहुंच रही है। जो हमें यह भी बताता है कि नीति और प्रवर्तन के बीच खाई में पर्यावरणीय अपराध कैसे और किस तेजी से पनपते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे खुदाई करने वाली भारी मशीनों का खुलेआम प्रयोग अवैध खनन हेतु किया जा रहा है। इस पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र की पूरी पहाड़ियों को समतल किया जा रहा है। जो हमारे पर्यावरण के लिये एक गंभीर चुनौती है। यह क्षति शिवालिक पहाड़ियों के मूल पारिस्थितिक कार्यों मसलन भूजल पुनर्भरण, मृदा-स्थिरता और जैव-विविधता संरक्षण जैसे जीवन रक्षक लक्ष्यों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। दरअसल, यह शिवालिक पर्वतमाला भू-संरचना की दृष्टि से नयी बनी हुई है और स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। निर्विवाद रूप से किसी भी स्थान पर होने वाली अनियंत्रित खुदाई से भूमि का कटाव बहुत तेजी से होता है। जिसके चलते वर्षा ऋतु और उसके बाद भूस्खलन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती है। वहीं इन क्षेत्रों में गाद जमाव का संकट भी गहरा जाता है। कालांतर इसके चलते जल निकासी के पैटर्न में अप्रत्याशित बदलाव देखने में आता है। यह सर्वविदित है कि एक बार इन पहाड़ियों को अवैध रूप से काटकर समतल कर दिया जाता है तो उसके मूल स्वरूप को फिर प्राप्त कर पाना लगभग असंभव है। दूसरे शब्दों में कहें उस क्षेत्र विशेष का प्राकृतिक संरक्षण कवच हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ऐसे में प्राकृतिक सुरक्षा को नष्ट करने वाला विकास कालांतर आपदा का कारक बन सकता है। दरअसल, यह ऐसा प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र होता है जो निचले मैदानी इलाकों को बाढ़ और जल संकट से बचाता है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि इस बाबत जवाबदेह अधिकारियों द्वारा दलील दी जाती रही है कि इस क्षेत्र में खनन की प्रक्रिया पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों के आधार पर की जाती रही है। साथ ही यह भी सफाई दी जाती है कि ऐसी स्वीकृतियों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन हकीकत तब उजागर हो जाती है जब स्थानीय लोग रात के समय होने वाले खनन कार्यों, निर्धारित सीमा से अधिक और बड़े पैमाने पर पहाड़ी इलाकों में कटाई होने के आरोप लगाते हैं। ऐसे में अधिकारियों की तमाम दलीलें खोखली ही साबित होती हैं। दरअसल,सवाल नियम-कानूनों की प्रभावकारिता का नहीं है बल्कि असली दिक्कत प्रवर्तन एजेंसियों की उदासीनता की है। जो वस्तु-स्थिति से अवगत होने के बावजूद इन आपराधिक कृत्यों के प्रति आंखें मूंदे रहती हैं। दरअसल, खनन कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को आपराधिक तत्वों व राजनेताओं का संरक्षण भी एक बड़ी चुनौती है। इसमें दो राय नहीं है कि जब अवैध खनन के खिलाफ जमीनी स्तर पर निगरानी के बजाय महज कागजी कार्रवाई का सहारा लिया जाता है तो अवैध खनन को संबल मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि यह अवैध खनन केवल पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों के आसपास ही हो रहा है। पूरे भारत में, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तमाम क्षेत्रों में अवैध खनन लगातार पर्यावरण से जुड़े कानूनों की सीमाओं का उल्लंघन करता नजर आता है। अकसर खनन के लिये दिए गए परमिटों में अस्पष्टता और स्थानीय स्तर पर कमजोर निगरानी का फायदा उठाया जाता है।

बच्चों को ऐश की चाबियाँ माता पिता की जिम्मेदारी और समाज की चेतना

(लेखक -कांतिलाल मांडोत)

सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी केवल एक मामले तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे समाज के लिए चेतावनी की तरह है कि बच्चों को बिना जिम्मेदारी सिखाए सुविधाओं की चाबी सौंप देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है ।पुणे के चर्चित नाबालिग कार चालक दुर्घटना मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जो कहा वह हमारे सामाजिक ढांचे पर सीधा सवाल खड़ा करता है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते जब वे संवाद नहीं कर पाते तब वे पैसे और सुविधाओं से उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और यही प्रवृत्ति आगे चलकर गंभीर सामाजिक समस्या बन जाती है।

न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि नाबालिगों को कार की चाबियां देना महंगे शौक पूरे करने के लिए बेहिसाब पैसा देना और उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण न रखना केवल व्यक्तिगत चूक नहीं है बल्कि यह सामूहिक लापरवाही का प्रतीक है ।आज के शहरी समाज में यह पैटर्न बार बार सामने आ रहा है। जहां कम उम्र के बच्चे देर रात पार्टियों में शामिल होते हैं ,शराब और नशे के संपर्क में आते हैं। तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं। और निर्दोष लोगों की जान खतरे में डाल देते हैं। इसके बाद जब दुर्घटना होती है तो प्रभाव और पैसे के बल पर सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की जाती है। मेडिकल साक्ष्य बदले जाते हैं। और कानून के शिकंजे से बचने के रास्ते तलाशे जाते हैं।

पुणे का यह मामला इसलिए भी झकझोरने वाला है क्योंकि इसमें दो युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की जान चली गई जो अपने भविष्य के सपने संजोए हुए थे। एक पल की लापरवाही ने उनके परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। अदालत ने जिन तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की वे सबूत मिटाने और रक्त के नमूने बदलने जैसे गंभीर आरोपों में घिरे थे ।यह दर्शाता है कि समस्या केवल नाबालिग की नहीं बल्कि पूरे तंत्र की है जहां अपराध के बाद भी सच को दबाने की कोशिश होती है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सबसे अहम पहलू यह है कि उसने जिम्मेदारी का केंद्र माता पिता को माना है ।न्यायालय ने कहा कि माता पिता के पास बच्चों से बात करने का समय नहीं होता यही मूल समस्या है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा की दौड़ में माता पिता यह भूल जाते हैं कि बच्चों के साथ समय बिताना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ।जब संवाद टूटता है तो बच्चे मोबाइल फोन क्रेडिट कार्ड और महंगी गाड़ियों के सहारे अपनी मर्जी की दुनिया बना लेते हैं ।उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है।

आज भारत में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं के आंकड़े डराने वाले हैं ।वर्ष 2023 24 में ऐसे लगभग बारह हजार हादसे दर्ज किए गए जिनमें हजारों लोगों की जान गई। यह केवल संख्या नहीं है बल्कि हजारों परिवारों का दर्द है। हर दुर्घटना के पीछे एक कहानी है किसी मां की सूनी गोद किसी पिता का टूटा सहारा और किसी बच्चे का अधूरा बचपन यह आंकड़े बताते हैं कि कानून के साथ साथ सामाजिक चेतना की भी सख्त जरूरत है।

कानून पहले से मौजूद है मोटर वाहन अधिनियम नाबालिगों के वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाता है और हाल के वर्षों में अभिभावकों पर भी जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है लेकिन कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक समाज उसे स्वीकार न करे। जब तक माता पिता यह न समझें कि प्यार का मतलब हर मांग पूरी करना नहीं है बल्कि सही और गलत के बीच फर्क सिखाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इसे गंभीर सामाजिक समस्या बताया है,वह हमें आत्ममंथन के लिए मजबूर करता है क्या हम बच्चों को केवल सुविधाएं दे रहे हैं या संस्कार भी क्या हम उन्हें यह सिखा रहे हैं कि सड़क पर चल रही हर गाड़ी के सामने एक इंसान की जिंदगी होती है क्या? हम उन्हें यह समझा पा रहे हैं कि कानून से बचना चतुराई नहीं बल्कि कायरता है।

आज जरूरत इस बात की है कि परिवार स्कूल और समाज मिलकर बच्चों के लिए एक जिम्मेदार वातावरण तैयार करें माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के साथ समय बिताएं उनकी बात सुनें उनकी जिज्ञासाओं को समझें और सीमाएं तय करें ।बच्चों को स्वतंत्रता मिले लेकिन उम्र और समझ के अनुसार मिले। स्कूलों में सड़क सुरक्षा और नागरिक जिम्मेदारी को केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बल्कि व्यवहार का हिस्सा बनाया जाए। समाज को भी ऐसे मामलों में चुप्पी तोड़नी होगी प्रभाव और पैसे के दबाव में गलत को सही ठहराने की प्रवृत्ति पर रोक लगानी होगी।

मीडिया और सोशल मीडिया की भी भूमिका अहम है जहां एक ओर तेज रफ्तार और लग्जरी लाइफस्टाइल का महिमामंडन होता है वहीं दूसरी ओर उसके दुष्परिणामों को उतनी गंभीरता से नहीं दिखाया जाता। युवाओं को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि असली स्टाइल जिम्मेदारी में है न कि नियम तोड़ने में।

सुप्रीम कोर्ट का यह संदेश स्पष्ट है कि अब नरमी का दौर खत्म होना चाहिए कानून को उन लोगों पर शिकंजा कसना होगा जो अपने बच्चों की गलतियों को ढाल बनकर ढकते हैं। लेकिन उससे भी पहले समाज को यह समझना होगा कि भविष्य की सुरक्षा आज की जिम्मेदारी से जुड़ी है यदि आज हम बच्चों को ऐश की चाबियां थमा देंगे तो कल वे उन चाबियों से न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल सकते हैं।

अंत में यही कहा जा सकता है। कि यह मामला एक चेतावनी है। एक अवसर है खुद को सुधारने का माता पिता के लिए यह समय है रुककर सोचने का कि वे अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। केवल पैसा और सुविधाएं या समय संस्कार और जिम्मेदारी यदि हम इस सवाल का ईमानदारी से जवाब ढूंढ लें तो शायद सड़कों पर मासूम जिंदगियां बच सकें। और समाज एक सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ सके।

(रु03 जलवन्त टाऊनशिप पूणा बॉम्बे मार्केट रोड, नियर नन्दालय हवेली सूरत मो 99749 40324 वरिष्ठ पत्रकार,सहित्यकार-स्तम्भकार)

राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व

आर्थिक और सामाजिक असमानता राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधा है। उस असमानता का मूल है अहं और स्वार्थ। इसलिए राष्ट्र की भावात्मक एकता के लिए अहं-विसर्जन और स्वार्थ-विसर्जन को मैं बहुत महत्व देता हूं। जातीय असमानता भी राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा विघ्न है। उसका भी मूल कारण अहं ही है। दूसरों से अपने को बड़ा मानने में अहं पुष्ट होता है और आदमी अपने-आप में संतोष का अनुभव करता है। अहं का विसर्जन किए बिना जातीय भेद का अंत नहीं हो सकता। मनुष्य जन्मना मनुष्य का शत्रु नहीं है। एक पेड़ की दो शाखाएं परस्पर विरोधी कैसे हो सकती हैं? फिर भी यह कहा जाता है कि धर्म-संप्रदाय मनुष्यों में मैत्री स्थापित करने के लिए प्रचलित हुए हैं। उनमें जन्मना शत्रुता नहीं है, फिर मैत्री स्थापित करने की क्या आवश्यकता हुई? मैं फिर इस विश्वास को दोहराना चाहता हूं कि मनुष्य-मनुष्य में स्वभावतः शत्रुता नहीं है।

वह निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा उत्पन्न की जाती है। उसे मिटाने का काम धर्म-संप्रदाय ने प्रारंभ किया, किंतु आगे चलकर वे स्वयं निहित स्वार्थ वाले लोगों से घिर गए और मनुष्य को मनुष्य का शत्रु मानने के सिद्धांत की पुष्टि में लग गए। इस चिंतन के आधार पर मुझे लगता है कि सांप्रदायिक समस्या का मूल भी अहं और स्वार्थ को छोड़कर अन्यत्र नहीं खोजा जा सकता। इसलिए सांप्रदायिक वैमनस्य की समस्या को सुलझाने के लिए भी अहं और स्वार्थ का विसर्जन बहुत आवश्यक है।

भाषा, जो दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाने का माध्यम है, को भी राष्ट्रीय एकता के सामने समस्या बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। अपनी भाषा के प्रति आकर्षण होना अस्वाभाविक नहीं है। पर हमें इस तथ्य को नहीं भुला देना चाहिए कि मातृभाषा के प्रति जितना हमारा आकर्षण होता है, उतना ही दूसरों को अपनी मातृभाषा के प्रति होता है। इसलिए भाषाई अभिनिवेश में फंसना कैसे तर्कसंगत हो सकता है। राष्ट्रीय एकता के लिए इन विषयों पर गंभीर चिंतन करना आवश्यक है।

विचार मंथन

वैश्विक कूटनीति में बदलता शक्ति संतुलन

(लेखक- डॉ हिदायत अहमद खान)

मौजूदा वक्त में विकसित देशों के साथ ही प्रमुख विकासशील देशों में जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, उससे दुनियां में एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। मनमाने ढंग से देशों पर अपने नियमों को लादना और न मानने पर कठोर से कठोर कार्यवाही करना, सामान्य लगने लगा है। न्याय दिलाने या जुल्म को खत्म करने की बजाय शक्ति का उपयोग अपने आधिपत्य को बढ़ाने के लिए किया जाने लगा है। इस तरह से इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक दुनियां की तस्वीर बदलने को आतुर नजर आ रहा है। वैश्विक राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिख रही है। यही नहीं लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का नेतृत्व करने वाला अमेरिका अब धीरे-धीरे कई बहुपक्षीय मंचों और वैश्विक संस्थानों से पीछे हटता नजर आया है। इसके विपरीत, चीन इस खाली होते कूटनीतिक मैदान में न केवल सक्रिय हुआ है, बल्कि स्वयं को एक वैकल्पिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि भविष्य का वैश्विक सुपर पावर कौन होगा, अमेरिका, रुस, चीन या कोई और उभरती ताकत? अमेरिका में दूसरी बार बने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वर्ष के कार्यकाल में 66 बहुपक्षीय संगठनों से बाहर निकलने की घोषणा करके सभी को चौंकाने का काम किया है। इससे वैश्विक राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। जलवायु परिवर्तन, श्रम अधिकार और प्रवासन जैसे मुद्दों को 'राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध' बताकर उनसे दूरी बनाना अमेरिका की उस परंपरागत भूमिका से हटना है, जिसमें वह वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के संरक्षक की भूमिका निभाता चला आ रहा था। फिलहाल इस बदलाव का लाभ चीन को मिला है, जिसने कूटनीतिक स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बीजिंग में विदेशी नेताओं की मेजबानी के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह कहना, कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था भारी दबाव में है और समानता आधारित प्रणाली की जरूरत है, चीन की महत्वाकांक्षा को स्पष्ट करता है। वैसे चीन इस दिशा में लंबे समय से काम करता चला आया है। खास बात यह है कि चीन का उभार केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में यह धारणा मजबूत हुई है कि आने वाले दशकों में चीन का वैश्विक प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में अमेरिका और चीन के बीच शक्ति का जो अंतर कभी बहुत व्यापक था, वह अब सिमट रहा है। हालांकि सैन्य क्षमता, तकनीकी नवाचार और सॉफ्ट पावर के लिहाज से अमेरिका अब भी अग्रणी है, लेकिन चीन आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर उसकी बराबरी बल्कि कई मामलों में तो आगे बढ़ता दिखा है।

इस वैश्विक रणनीति में 'ग्लोबल साउथ' की भूमिका बेहद अहम है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के साथ चीन ने बीते एक दशक में गहरे संबंध बनाए हैं। वर्ष 2013 में शुरू किया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) इसी का सशक्त उदाहरण है, जिसके तहत चीन ने बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है। आज जब पश्चिमी देश चीन को रणनीतिक रूप से घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तब यही विकासशील देश उसके लिए राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन का आधार बनते दिख रहे हैं। आर्थिक रूप से भी चीन की स्थिति मजबूत बनी हुई है, 2025 में पांच प्रतिशत की विकास दर और रिकॉर्ड व्यापार अधिशेष इसकी पुष्टि करते हैं।

बावजूद इसके अमेरिका के सामने चीन का यह रास्ता जोखिमों से मुक्त नहीं है। अमेरिका टैरिफ-टैरिफ खेल रहा है, जबकि कई देशों में बीआरआई परियोजनाओं से जुड़े कर्ज संकट ने चीन को अपनी निवेश नीति पर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि अब वह बड़े और जोखिम वाले प्रोजेक्ट्स के बजाय छोटे, सुरक्षित और रणनीतिक निवेशों पर ध्यान दे रहा है। इसके साथ ही रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ाई है। यह साझेदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर नहीं, बल्कि अमेरिका-विरोध जैसे तात्कालिक हितों पर आधारित प्रतीत होती है, जिसका असर संयुक्त राष्ट्र में समन्वित मतदान के रूप में दिखता है। यहां महत्वपूर्ण यह भी है कि चीन पूरी वैश्विक व्यवस्था पर वर्चस्व स्थापित करने की जल्दबाजी में नहीं दिखता। फिलहाल बीजिंग की प्राथमिकता अपनी घरेलू राजनीतिक स्थिरता और कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को सुरक्षित रखना है। इस दिशा में भी उसने मौजूदा वक्त में अनेक सख्त फैसले लिए हैं और अनेक जिम्मेदारों को सजा तक देने से पीछे नहीं हटा है। वह केवल उन्हीं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है, जहां उसके प्रत्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा हित जुड़े हों। असल में चीन का लक्ष्य वैश्विक प्रभुत्व से अधिक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करना है, जिसकी झलक दक्षिण चीन सागर में बढ़ती सैन्य गतिविधियों से भी मिल जाती है। अंततः आज की दुनिया एक एकध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय संतुलन की ओर बढ़ रही है। अमेरिका और चीन के बीच यह प्रतिस्पर्धा केवल शक्ति की नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की दिशा तय करने की भी है। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि दुनिया किसी एक सुपर पावर के नेतृत्व को स्वीकार करती है या साझा, संतुलित और बहुपक्षीय व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाती है।

नेस्ले इंडिया की मैगी के 50 वर्ष पूरे, स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी

नई दिल्ली । नेस्ले इंडिया के लोकप्रिय ब्रांड मैगी ने भारत में अपनी उपस्थिति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस डाक टिकट का अनावरण केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और नेस्ले इंडिया के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष तिवारी ने एक गरिमामयी समारोह में किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस अवसर पर कहा कि मैगी जैसे अग्रणी ब्रांड्स ने भारतीय खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने और उपभोक्ताओं का विश्वास जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ब्रांड की पांच दशकों की विकास यात्रा की सराहना की। नेस्ले इंडिया के एमडी मनीष तिवारी ने इसे उपभोक्ताओं के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 50 ईयर्स ऑफ़ टुगेदरनेस डाक टिकट उन अनगिनत साझा पलों को समर्पित है, जो मैगी ने पीढ़ियों से भारतीय घरों में निर्मित किए हैं। पिछले पांच दशकों में मैगी ने नूडल्स से लेकर सॉस और सूप तक अपनी श्रेणियों का विस्तार कर हर वर्ग के स्वाद में अपनी जगह बनाई है। कंपनी ने भविष्य में भी इसी विश्वास और गुणवत्ता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, 723.8 अरब डॉलर

- पिछले सप्ताह के 709.41 अरब डॉलर से 14.4 अरब डॉलर अधिक

मुंबई । भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 30 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 723.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। यह पिछले सप्ताह के 709.41 अरब डॉलर से 14.4 अरब डॉलर अधिक है। इससे पहले 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भंडार में 8.05 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा* ने कहा कि यह भंडार लगभग 11 महीने के वस्तु आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की बाहरी वित्तीय स्थिति मजबूत है और देश अपनी विदेशी वित्तीय जरूरतों को आसानी से पूरा करने में सक्षम है। विदेशी मुद्रा भंडार में चार कारक हैं - विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि और विशेष आहरण अधिकार। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में करीब 563 अरब डॉलर पर और स्वर्ण भंडार 123 अरब डॉलर पर था। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में डॉलर के अलावा यूरो, ब्रितानी पाउंड और जापानी येन शामिल होता है। आरबीआइई के अनुसार, भंडार की यह बढ़त भारत को वैश्विक वित्तीय बाजारों में भरोसा और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और स्वर्ण के उच्च स्तर से भारत अपनी बाहरी भुगतान क्षमता बनाए रखने में सक्षम है।

कॉग्निजेंट ने कर्मचारियों को 100 फीसदी बोनस दिया, राजस्व वृद्धि में रिकॉर्ड प्रदर्शन

नई दिल्ली । कॉग्निजेंट ने वर्ष 2025 में 6.4 फीसदी की राजस्व वृद्धि दर्ज की, जो कंपनी के अनुमान 6-6.3 फीसदी से अधिक है। कंपनी ने इसेविजेताओं के समूह में शामिल होने जैसा अनुभव बताया। कंपनी के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने कहा कि कंपनी नैस्डैक में सूचीबद्ध शीर्ष राजस्व वृद्धि वाली कंपनियों में फिर से शामिल हो गई है। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने प्रदर्शन के चलते कर्मचारियों को 100 फीसदी बोनस दिया, जो पिछले सात वर्षों में सबसे बड़ा है। इससे यह जाहिर होता है कि कॉग्निजेंट कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए गंभीर है। कंपनी ने राजस्व वृद्धि, बाजार हिस्सेदारी, बड़े करार की गति, कौशल प्रशिक्षण, मार्जिन विस्तार और प्रति शेयर कमाई में बढ़ोतरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया।

चांदी दो दिन में 41 हजार सस्ती, सोना भी धड़ाम

-चांदी की कीमत 2.41 लाख/किलो, तो सोना 1.51 लाख पर आया

नई दिल्ली।

सोने-चांदी के दाम में शुक्रवार को भी गिरावट जारी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत शुक्रवार को 13,155 रुपए गिरकर 2,41,184 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,54,339 रुपए थी। दो दिन में ये 41,278 रुपए सस्ती हो चुकी है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,013 रुपए कम होकर 1,51,489 रुपए पर आ गया है। इससे पहले ये 1,52,502 रुपए पर था। सोना दो दिन में 6,669 रुपए सस्ता हुआ है। सर्राफा बाजार में सोने ने 29 जनवरी को 1,76,121 और चांदी ने 3,85,933 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था।

इससे पहले 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच चांदी की कीमत 1.60 लाख रुपए कम हुई थी। वहीं, सोने की कीमत में 26 हजार रुपए कम हुई थी। वायदा कारोबार पर चांदी 4 लाख रुपए से घटकर 2.41 रुपए प्रति किलो पर आ गई थी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1.70 लाख से गिरकर 1.40 लाख पर आ गया था। हालांकि फिर दोनों के दाम में तेजी रही थी।

सोने-चांदी में गिरावट की वजह

सोने-चांदी की कीमत हाल के दिनों में

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया। वहीं ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएं भी बढ़ीं।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई । भारतीय रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 34 पैसे की गिरावट के साथ ही 90.68 पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 90.23 पर पहुंच गया। गुरुवार को रुपया 13 पैसे बढ़कर 90.34 पर बंद हुआ था। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में कारोबार के दौरान रुपया 90.28 पर खुला और फिर बढ़त जारी रखी। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने रुपया में और अधिक तेजी पर रोक लगाई। वहीं, डॉलर में थोड़ी मजबूती के चलते भी स्थानीय मुद्रा की बढ़त सीमित रही।

आरबीआई डिजिटल लेन-देन सुरक्षा और ग्राहक क्षतिपूर्ति के लिए बनाएगा नई रूपरेखा

- छोटे-मोटे धोखाधड़ी वाले लेन-देन में 25,000 तक की क्षतिपूर्ति

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को घोषणा की कि छोटे मूल्य वाले धोखाधड़ी वाले डिजिटल लेन-देन के लिए ग्राहकों को 25,000 तक की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसका उद्देश्य ग्राहकों की तत्काल सुरक्षा और विश्वास बढ़ाना है। आरबीआई जल्द ही एक परिचर्चा पत्र प्रकाशित करेगा जिसमें डिजिटल भुगतान सुरक्षा के उपाय शामिल होंगे। इसमें विलंब से क्रेडिट और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण जैसी सुविधाएं होंगी। तीन दिशानिर्देशों का मसौदा` किया जाएगा तैयार- वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री रोकना, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन में ग्राहक की देनदारी सीमित करना और ऋण वसूली और वसूली एजेंट के दिशा-निर्देशों का सामंजस्य। शहरी सहकारी बैंकों की क्षमता निर्माण के लिए मिशन सक्षम की शुरुआत की जाएगी। मल्होत्रा ने कहा कि सभी नए और संशोधित निर्देश जल्द सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे, जिससे बैंकिंग क्षेत्र और डिजिटल भुगतान प्रणाली अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बने।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 266 अंक, निफ्टी 50 अंक उछला

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी दिन बढ़त पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के बाद भी खरीदारी हावी होने से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 266.47 अंक उछलकर 83,580.40 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 50.90 अंक बढ़कर 25,693.70 पर बंद हुआ। आज एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयरों में उछाल से बाहर ऊपर आया है। आईटीसी के शेयरों में 5 फीसदी और एचयूएल में 2.96 फीसदी की बढ़त रही।

आज कारोबार के दौरान निफ्टी एफएमसीजी , निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी रियल्टी , निफ्टी के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं निफ्टी

आईटी , निफ्टी फार्मा , निफ्टी इंडिया डिफेंस , निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी ऑटो शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स पैक में आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, टाइटन, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एमएंडएम और एलएंडटी के शेयर लाभ में रहे जबकि टेक महिंद्रा, टीसीएस, एशियन पेंट्स, इटरनल, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और बीईएल के शेयरों को नुकसान हुआ। लार्जकैप की जगह मिडकैप और स्मॉलकैप के शेयरों में बिकवाली हावी रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 14.40 अंक की गिरावट के साथ 59,502.70 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 45.25 अंक टूटकर 16,938.65 पर था। इससे पहले आज सुबह बाजार गिरावट के साथ खुले। सुबह शुरुआत के बाद सेंसेक्स 224.17 अंक गिरकर 83,089.76 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी-50 25,605 पर खुला और जल्द ही 25,600 के नीचे फिसल गया। वहीं एशियाई बाजारों में गिरावट रही। वॉल स्ट्रीट पर भी टेक शेयरों में दबाव रहा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, टेक शेयरों वाला नैस्डैक 100 पिछले साल अप्रैल के बाद तीन दिनों में सबसे बड़ी गिरावट का सामना कर रहा है। इसकी एक वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चिंता भी है। इस दौरान एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.23 फीसदी और नैस्डैक 1.59 फीसदी के नीचे बंद हुआ।

भारत में 'डोल्से' ब्रांड की एंट्री, फाइन एर्स और व्यंडहम में रणनीतिक गठबंधन

उदयपुर और गोवा में खुलेंगे लग्जरी रिसॉर्ट्स; राजस्थान में 'व्यंडहम ग्रैंड' का भी हुआ औपचारिक आगाज

उदयपुर ।

भारतीय हॉस्पिटैलिटी परिदृश्य में एक नए युग की शुरुआत करते हुए देश की अग्रणी रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी कंपनी फाइन एर्स ने विश्व की विशालतम होटल फ्रेंचाइजिंग संस्था व्यंडहम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के साथ एक ऐतिहासिक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। इस साझेदारी के माध्यम से प्रतिष्ठित वैश्विक ब्रांड डोल्से होटल्स एंड रिसॉर्ट्स पहली बार भारतीय बाजार में कदम रखने जा रहा है।

संस्थापक व प्रबंध निदेशक दिनेश यादव के नेतृत्व में विकसित इस सहयोग के तहत गोवा और उदयपुर में दो फ्लैगशिप परियोजनाएं डोल्से बाय व्यंडहम लॉन्च की गई हैं।

उदयपुर के कोडियात में आयोजित एक भव्य गाला साइनिंग समारोह में इस गठबंधन पर मुहर लगी, जिसमें बॉलीवुड हस्तियों, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और उद्योग जगत के दिग्गजों ने शिरकत की। इसी अवसर पर व्यंडहम ग्रैंड जयपुर आमेर का भी शुभारंभ किया गया, जो राजस्थान की शाही विरासत के साथ वैश्विक आधुनिकता का समावेश है।

इन परियोजनाओं की मुख्य विशेषता इनका यूनिट सेल्स मॉडल है।

इसके अंतर्गत लगभग 70 प्रतिशत इकाइयां व्यक्तिगत निवेशकों को विक्रय की जाएंगी, जिन्हें एक प्रबंधित रेंटल पूल के माध्यम से पूर्णतः लीज-बैक किया जाएगा। यह मॉडल निवेशकों के लिए व्यावसायिक स्थिरता, पेशेवर संचालन और दीर्घकालिक मूल्य सृजन सुनिश्चित करता है।

प्रबंध निदेशक दिनेश यादव ने कहा, हमारा लक्ष्य भारत में 5,000 यूनिट्स के विस्तार के साथ विश्व-स्तरीय हॉस्पिटैलिटी अनुभव प्रदान करना है। डोल्से ब्रांड प्रीमियम रिसॉर्ट्स और डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने की दिशा में हमारा एक ठोस कदम है। व्यंडहम के प्रेसिडेंट दिमित्रिस मैनिकिस और यूरेशिया के एमडी राहुल मैकारियस ने इसे गेम-चेंजर बताते हुए कहा कि यह साझेदारी पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

आरबीआई बैंकों को रीट को ऋण देने की अनुमति देने पर कर रहा विचार

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को रियल एस्टेट क्षेत्र के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकों को रील एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) को ऋण देने की अनुमति देने का प्रस्ताव पेश किया। इस कदम के पीछे मकसद है निवेशकों और बैंकों दोनों के लिए वित्तीय तरलता बढ़ाना। रीट ऐसे निवेश माध्यम हैं जो आय उत्पन्न करने वाली रियल एस्टेट संपत्तियों के मालिक होते हैं या उनका संचालन करते हैं। निवेशक सीधे संपत्ति खरीदे बिना संपत्ति से होने वाली आय में हिस्सा ले सकते हैं। भारत में रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की अवधारणा संस्थागत और खुदरा निवेशकों के कोष के माध्यम से निवेश पुनर्वित्त करने और बैंकों के फंसे कोष को मुक्त करने के लिए बनाई गई थी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक मौद्रिक नीति में कहा कि कुछ विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ बैंकों को रीट को ऋण देने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में, केवल इर विट को बैंक ऋण की अनुमति है, जबकि रीट को यह अनुमति नहीं थी। प्रस्तावित कदम में रीट को ऋण देने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को इन विट के समान किया जाएगा।

रेपो रेट में बदलाव नहीं, लोन महंगा नहीं होगा,

आरबीआई ने ब्याज दर 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखी, अब आरबीआई लाएगा सख्त गाइडलाइंस, लोन-रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे

एजेंटों की बदतमीजी बैंकों को पड़ेगी भारी

मुंबई।

इस बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है। इसे 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को मॉनीटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए फैसलों की जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन रिकवरी एजेंटों की मनमानी और बैंकों द्वारा की जा रही मिस-सेलिंग पर लगाम लगाने के लिए सख्त गाइडलाइंस लाने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि केंद्रीय बैंक तीन नए ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी करने जा रहा है। इनका मकसद ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करना और बैंकों की जवाबदेही तय करना है। इन नियमों के लागू होने के बाद रिकवरी एजेंट ग्राहकों को डरा-धमका नहीं पाएंगे और न ही बैंक आपको ऐसा इंश्योरेंस या लोन दे पाएंगे, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है कि लोन रिकवरी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नैतिकता लाने के लिए मौजूदा नियमों को और कड़ा किया जाएगा। अक्सर शिकायतें आती हैं कि रिकवरी एजेंट ग्राहकों को देर रात फोन करते हैं, उनके रिश्तेदारों को परेशान करते हैं या घर आकर बदतमीजी करते हैं। नए नियमों के तहत बैंक अब इन एजेंटों की हरकतों के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे। अगर कोई एजेंट नियमों का उल्लंघन करता है, तो बैंक पर भारी जुर्माना लग सकता है।

अब जबरदस्ती नहीं बेच पाएंगे इंश्योरेंस

जब कोई ग्राहक बैंक में एफडी कराने या लोन लेने जाता है, तो बैंक कर्मचारी उसे लुभावने वादे करके कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट प्लान बेच देते हैं। बाद में पता चलता है कि वह प्रोडक्ट ग्राहक के लिए फायदेमंद ही नहीं था। इसे ही मिस-सेलिंग कहते हैं। आरबीआईअब इसके लिए सख्त गाइडलाइंस तय कर रहा है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ग्राहकों को वही प्रोडक्ट बेचें जो उनकी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार हो।

डिजिटल फ्रॉड पर 25,000 तक का मुआवजा

रिजर्व बैंक ने एक नया फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत छोटे अमाउंट वाले फ्रॉड ट्रांजैक्शन में नुकसान झेलने वाले ग्राहकों को 25 हजार तक का मुआवजा दिया जाएगा।

नई दिल्ली में लॉन्च हुई भारत टैक्सी, देश की पहली सहकारी कैब सर्विस

मुंबई।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सीऐप को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। यह देश की पहली सहकारी कैब सर्विस है, जो प्रॉफिट के बजाय ड्राइवरों के कल्याण पर केंद्रित है। कंपनी किसी भी तरह का कमीशन नहीं लेती, और राइड का पूरा पैसा सीधे ड्राइवर के खाते में जाता है। भारत टैक्सी में कैब के साथ-साथ मेट्रो टिकट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। सहकारी मॉडल और कमीशन रहित सिस्टम के कारण किराया ओला-उबर की तुलना में काफी कम है। साथ ही ऐप में सर्ज प्राइसिंग का कोई सिस्टम नहीं है, जिससे भीड़ के समय किराया बढ़ता नहीं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐप में एसओएस, इमरजेंसी बटन भी दिया गया है, जो लोकेशन भरोसेमंद संपर्कों तक तुरंत भेजता है। सफल ट्रायल के बाद ऐप अब दिल्ली-एनसीआर में पूरी तरह

उपलब्ध है और जल्द ही मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु में भी शुरू होगा।

आरबीआई ने छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ाई कोलैटरल-फ्री लोन की सीमा

- कोलैटरल-फ्री लोन सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की

मुंबई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद छोटे कारोबारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। आरबीआई ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (एमएसई) के लिए कोलैटरल-फ्री लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और उसके बाद स्वीकृत या रिन्यू होने वाले सभी लोन पर लागू रहेगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्यमियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे अधिक लोन उपलब्ध कराना और उन्हें औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। पहले कई छोटे व्यवसायियों को गिरवी की कमी के कारण महंगे अनौपचारिक कर्ज का सहारा लेना पड़ता था। अब वे आसानी से बैंक से 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे, जो मशीनरी खरीदने, स्टॉक बढ़ाने और कारोबार विस्तार में सहायक होगा। एमएसएमई सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और यह लाखों लोगों को रोजगार देता है। माइक्रो एंटरप्राइज में निवेश 2.5 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक होता है, जबकि स्मॉल एंटरप्राइज में निवेश 25 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ऋब्ढ़ का मानना है कि इस फैसले से छोटे उद्योगों को औपचारिक क्रेडिट सिस्टम से जोड़ने में मदद मिलेगी। आरबीआई का यह कदम न केवल छोटे कारोबारियों के लिए राहत देगा, बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में भी सहायक होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे एमएसएमई सेक्टर को विकास के नए अवसर मिलेंगे और कारोबारी निवेश में तेजी आएगी।

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारी गिरावट, बिटकॉइन 63,000 डॉलर के करीब

बिटकॉइन गुरुवार के मुकाबले 9 फीसदी और गिरकर 65,000 डालर के आसपास

मुंबई ।

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में पिछले दो दिनों से भारी अस्थिरता देखी जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन गुरुवार को 12.6 फीसदी गिरकर 63,300 डालर तक पहुंच गई, जो अक्टूबर 2024 के बाद का सबसे निचला स्तर है। शुक्रवार को बिटकॉइन करीब 9 फीसदी और गिरकर 65,000 डालर के आसपास ट्रेड करने लगी। इस हफ्ते बिटकॉइन में कुल 17 फीसदी और साल 2026 में अब तक 28 फीसदी की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ईथर भी दबाव में रही और एक दिन में 13 फीसदी से अधिक गिर गई, जबकि साल 2026 में इसमें करीब 38 फीसदी की गिरावट हो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशकों की जोखिम से दूरी, भारी लिक्विडेशन और अमेरिकी मौद्रिक नीति में सख्ती की आशंकाओं ने बाजार को झटका दिया। कॉइनग्लास के आंकड़ों के

मुताबिक केवल 24 घंटों में 1 बिलियन डालर के बिटकॉइन पोजीशन जबरन बंद हुए। इसके अलावा टेक शेयरों में कमजोरी और सोना-चांदी जैसी संपत्तियों में अस्थिरता ने बाजार दबाव और बढ़ाया। संस्थागत निवेशकों द्वारा क्रिप्टो ईटीएफ से लगातार निकासी भी गिरावट का बड़ा कारण बनी है। डॉयचे बैंक के अनुसार, जनवरी में अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ से 3 बिलियन डालर से ज्यादा निकासी हुई। बाजार के जानकारों के अनुसार, क्रिप्टो बाजार फिलहाल कैपिटुलेशन मोड में है। यह केवल अल्पकालिक सुधार नहीं बल्कि बड़े रीसेट की शुरुआत हो सकता है, जो कई महीनों तक चल सकता है। गिरावट जारी रहने पर माइनर्स पर दबाव बढ़ सकता है और जबरन लिक्विडेशन का जोखिम फिर से बढ़ सकता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टी20 विश्वकप में आज अमेरिका पर जीत के साथ अपना अभियान शुरु करने उतरेगी भारतीय टीम

मुंबई (एजेंसी)। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम शनिवार को यहां टी20 विश्वकप के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ जीत से शुरुआत करने उतरेगी। भारतीय टीम ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 4-1 से जीत दर्ज की है जिससे उसके हौंसले बुलंद हैं। भारतीय टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज अच्छे फार्म में हैं जिसका लाभ उसे मिलेगा। भारतीय टीम के पास अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसी आक्रामक जोड़ी हैं। तिलक वर्मा की वापसी से भी टीम की बल्लेबाजी मजबूत हुई है। वहीं टीम की गेंदबाजी अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती पर आधारित रहेगी। ऐसे में वह जीत की प्रबल दावेदार नजर आती है।

कप्तान सूर्यकुमार भी इस साल की शुरुआत से ही फार्म में आ गये हैं जिसका भी लाभ टीम को मिलेगा। ईशान किशन ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पिछले कुछ समय में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ईशान और अभिषेक शर्मा की जोड़ी भारतीय टीम को धमाकेदार शुरआत दे सकती है।

टीम के पास हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल जैसे ऑल राउंडर हैं। रिंकू सिंह का फार्म में होना भी टीम के लिए सकारात्मक बात है। गेंदबाजी में बुमराह का साथ देने के लिए अर्शदीप सिंह भी हैं। हर्षित राणा हालांकि चोटिल होने के कारण इस मैच में नहीं रहेंगे। टीम के पास कुलदीप यादव और वरूण चक्रवर्ती जैसा स्पिनर है।

भारतीय टीम को अपने घरेलू मैदान का भी लाभ मिलेगा। इसके बाद भी वह अमेरिकी टीम को हल्के में नहीं लेगी। अमेरिकी टीम ने पिछली बार पाकिस्तान हराने के बाद सुपर आठ में भारतीय टीम को भी कड़ी टक्कर दी थी। अमेरिकी टीम ने पिछले साल 9 में से आठ मैच

जीते हैं और टी20 विश्व कप से पहले श्रीलंका में तीन सप्ताह के शिविर में भाग लिया है। ऐसे में उसे कमजोर नहीं माना जा सकता। उसके पास कई अच्छे खिलाड़ी हैं। अमेरिकी टीम की कप्तानी भारतीय मूल के मोनांक पटेल के पास है। उन्हें साइतेजा मुक्कमल्ला तथा मिलिंद कुमार से पूरा सहयोग मिला। वहीं गेंदबाजी में सौरभ नेत्रावलकर, हरमीत सिंह जैसे खिलाड़ी हैं।

टीम इस प्रकार है

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती।

अमेरिका : मोनांक पटेल (कप्तान/विकेटकीपर), स्टीवन टेलर, शायन जहांगीर, एंड्रीज़ गौस, मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, जेसी सिंह, निश्थुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर और अली खान।

मंधाना को डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी के साथ ही मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड

वडोदरा (एजेंसी)। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में स्मृति मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने दूसरी बार खिताब जीत है। इस जीत के दौरान मंधान ने 87 रनों की आक्रामक पारी खेली जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। आरसीबी ने इससे पहले 2024 में डब्ल्यूपीएल का खिताब जीता है। आरसीबी को विजेता बनने पर 6 करोड़ का इनाम मिला। वहीं चौथी बार फाइनल में उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ का इनाम मिली। इसके अलावा स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और सोफी डिवाइन को भी पांच-पांच लाख रुपये की इनामी राशि मिली है। मंधाना ने लीग में सबसे अधिक 377 रन बनाये। वहीं सोफी डिवाइन ने 17 विकेट के साथ पर्पल कैप जीती। युवा खिलाड़ी नंदनी शर्मा ने भी 17 विकेट लिए जिसके लिए उस भी उभरती हुई खिलाड़ी का इनाम मिला। सोफी को मोस्ट वेल्युएबल प्लेयर और मोस्ट आईक्यू ऑफ द ईयर का इनाम मिला। नंदनी को साल की ईमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मुम्बई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस साल लीग में सबसे ज्यादा छक्के लगाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत पर 6 करोड़ की ईनामी राशि मिली जबकि उपविजेता दिल्ली को 3 करोड़ रुपये मिले। फेयर प्ले अवार्ड के तौर पर मुम्बई को पांच लाख का इनाम मिला है।

डब्ल्यूपीएल में सभी खिलाड़ियों को पांच लाख के इनाम दिये गये हैं। वहीं मैन ऑफ द मैच के लिए मंधाना हो ढाई लाख रुपये मिले हैं।

12 फरवरी के बाद भारत से खेलने तैयार हो जाएगा पाक : चेतन शर्मा

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) चयन समिति के पूर्व प्रमुख चेतन शर्मा ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) 12 फरवरी के बाद भारत से खेलने को तैयार हो जाएगा। चेतन के अनुसार पाकिस्तान सरकार और क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) का विश्वकप बहिष्कार का फैसला राजनीतिक है और इसमें बदलावा आना तय है। चेतन का ये बयान हैरानी भरा लगा है क्योंकि गत दिवस ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साफ कर दिया कि उनकी टीम टी20 विश्वकप में खेलेगी पर भारतीय टीम के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगी। वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को अब भी उम्मीद है कि पाकिस्तान के रुख में बदलाव होगा क्योंकि मैच न खेलने उसपर प्रतिबंध सहित कई अन्य प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को विश्वकप से बाहर किये जाने के विरोध में विश्वकप से नाम वापस लिया है। चेतन ने कहा, 'बांग्लादेश के खिलाड़ियों की क्या गलती थी? कोई नहीं। ये सब राजनीति है. बांग्लादेश में 12 तारीख को चुनाव हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस सामले में फैसला पलटेगा। पाक से एक बयान आएगा, जिसमें कहा जाएगा कि जनता की भावना को देखते हुए पाक टीम भारत से खेलेगी क्योंकि खेल को नुकसान नहीं होना चाहिये।' अभी का कड़ा रुख केवल बांग्लादेश चुनाव के कारण है। चुनाव के बाद शायद सेना प्रमुख भी कह दें कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए और मैच होना चाहिए।÷चयन समिति के पूर्व प्रमुख चेतन ने कहा कि बहिष्कार से सबसे अधिक नुकसान पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हो रहा है। उन्होंने कहा, ÷ पाक बोर्ड ने अभी तक आईसीसी को कुछ भी औपचारिक रूप से नहीं बताया है। इस मामले से खिलाड़ी संश मे हैं।÷ वहीं पीसीबी जो भी करे, भारतीय टीम इस मैच के लिए तय समय पर कोलंबो पहुंचेगी। भारतय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी साफ कर दिया कि टीम कोलंबो जाएगी और मैच खेलेगी। उन्होंने कहा, 'हमारा रुख साफ है हमने खेलने से इंकार नहीं किया। आईसीसी ने जो कार्यक्रम तय किया है। हम उसका पालन करेंगे।÷ पाक टीम ये मैच नहीं खेलती है तो भारतीय टीम को वाकओवर के तौर पर दो अंक मिल जाएंगे।

बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, सीएम नीतीश कुमार ने की तारीफ, सहवाग भी हुए गदगद

हरारे (एजेंसी)। वैभव सूर्यवंशी की 80 गेंदों पर खेली गई 175 रनों की विशाल पारी की बदौलत भारतीय अंडर-19 पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड के सामने 412 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को बधाई दी है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि आज अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच में बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया है। वे अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते भारतीय क्रिकेट की एक नई उम्मीद बन गए हैं। मेरी शुभकामना है कि वैभव भविष्य में भारतीय टीम के लिए नया कीर्तिमान रचें और देश का नाम रौशन करें।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा कि बिहार की शान, भारत का गौरव - वैभव सूर्यवंशी! अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में 175 रनों की शानदार पारी खेलकर आपने न केवल बिहार का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे देश को गर्व से सराबोर कर दिया है। आपकी मेहनत, लगन और प्रतिभा ने यह साबित कर दिया कि

बिहार के युवा किसी से कम नहीं हैं। आप हमारे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। आपको इस शानदार उपलब्धि के लिए ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं! आगे भी ऐसे ही देश और प्रदेश का मान बढ़ाते रहें।

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लिखा कि बिहार का लाल वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत-इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में 80 गेंदों में 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर न सिर्फ हाईएस्ट स्कोर बनाया, बल्कि एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने और 55 गेंदों में सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। बिहार से निकलकर

पूरी दुनिया में अपना नाम चमका रहा है

उन्होंने आगे कहा कि यह प्रदर्शन बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा है और यह संदेश भी कि प्रतिभा और मेहनत से बिहार का बेटा दुनिया में पहचान बना सकता है। वैभव आगे भी इसी तरह क्रिकेट के लिए नए कीर्तिमान रचें और बिहार एवं देश का गौरव बढ़ाते रहें। उनकी इस शानदार पारी के बाद, पूर्व क्रिकेटरों ने तुरंत उनकी उपलब्धि को सराहा और सोशल मीडिया पर अलग-अलग पोस्ट के जरिए उन्हें बधाई दी। इनमें वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, इयान बिशप और माइकल वॉन शामिल थे।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने X पर एक पोस्ट में सूर्यवंशी की प्रशंसा करते हुए कहा, 'वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाए। 15 चौके + 15 छक्के - बराबर चौके, बराबर छक्के, बराबर तबाही। सूर्यवंशी = सूर्य वंश से जन्मे। आज उन्होंने बिल्कुल सूर्यवंशी की तरह बल्लेबाजी की! धधकते हुए। बेकाबू। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने हर संभव कोशिश की। लेकिन आप सूर्य को नहीं रोक सकते। भारतीय क्रिकेट पर सूर्य उदय हो गया है! यह भविष्य की एक झलक है।'

मंधाना ने बुखार के बाद भी खेली डब्ल्यूपीएल की सबसे अच्छी पारी : कोच रंगराजन

वडोदरा (ईएमएस)। आरसीबी के कोच मलोलन रंगराजन ने कप्तान स्मृति मंधाना की शानदार बल्लेबाजी की सराहना की है। कोच ने कहा कि मंधाना ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) फाइनल की अब तक की सबसे अच्छी पारी खेली है। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स से मिले 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मंधाना ने 41 गेंदों में 87 रन बनाकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी अधिक रहा। मंधाना ने अपनी इस पारी में 12 चौके और 3 छक्के लगाए। यह इस टूर्नामेंट के फाइनल की अब तक की सबसे आक्रामक पारी रही है। मंधाना की ये पारी इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये उसने बीमार होने के बाद भी खेली। मंधाना को इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला है।

कोच रंगराजन ने कहा कि मंधाना ने डब्ल्यूपीएल फाइनल में अपनी सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेली। रंगराजन ने कहा कि मंधाना ने तेज़ बुखार से पीड़ित होने के बाद भी अच्छी पारी खेली। उन्होंने इसका प्रभाव अपनी पारियों पर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मंधाना ने अपनी सबसे अच्छी पारियों में से एक फाइनल के लिए बचाकर रखी थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हां, वह पिछले 12 महीनों से बहुत अच्छी फॉर्म में रही हैं। वह गेंद को अपने हिसाब से खेल रहीं थीं। मंधाना और जॉर्जिया के अर्धशतक और दोनों के बीच हुई शतकीय साझेदारी से आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हराकर दूसरी बार खिताब जीत लिया।

चोटिल हर्षित राणा की जगह इस भरोसेमंद खिलाड़ी को मिली भारत की टी20 विश्व कप टीम में जगह

मुंबई। भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच में घुटने की चोट के कारण शुक्रवार को टी20 विश्व कप से बाहर होना पड़ा और सूत्रों के मुताबिक उनकी जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इससे पहले स्वीकार किया था कि इस 24 साल के गेंदबाज की स्थिति अच्छी नहीं लग रही। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार राणा की जगह टीम में साथी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। सूर्यकुमार की बातों से पहले ही लगा कि मुख्य कोच गौतम गंभीर के पसंदीदा खिलाड़ियों में शामिल इस गेंदबाज के लिए समय पर ठीक होना मुश्किल है। भारतीय टीम विश्व कप में अपना अभियान शनिवार को अमेरिका के खिलाफ शुरू करेगी। सूर्यकुमार ने शुक्रवार को मैच पूर्व संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'राणा को अभी बाहर नहीं किया गया है, हमारे फिजियो उनका आकलन कर रहे हैं, लेकिन उनके चोट की स्थिति अच्छी नहीं लग रही है।' सूर्यकुमार यादव ने हालांकि इसे ज्यादा बड़ी समस्या नहीं माना था। उन्होंने कहा, 'चिंता की बात नहीं है, हमारे पास कल (शनिवार) के लिए 11 खिलाड़ी हैं। यह हालांकि निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा क्योंकि 15 खिलाड़ियों की टीम बहुत सोच-विचार के बाद बनाई जाती है और उसे भी काफी सोच-विचार के बाद ही शामिल किया गया था।' भारतीय कप्तान ने कहा, 'वह अगर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हम अलग-अलग संयोजन अपनाएंगे। हमारे पास इस टूर्नामेंट में सभी टीम के खिलाफ खेलने के लिए पर्याप्त खिलाड़ी और संयोजन मौजूद हैं। वह अगर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो हमें उनकी कमी निश्चित रूप से खलेगी।' राणा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच में केवल एक ओवर डाला जिसमें उन्होंने 16 रन दिए और उसके बाद घुटने की चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए। राणा हालांकि भारत की शुरुआती एकादश का हिस्सा नहीं थे। उनका 9 टी20 अंतरराष्ट्रीय में इकोनॉमी रेट भी 10.60 का है। वह हालांकि विशिष्ट परिस्थितियों में एक उपयोगी विकल्प साबित हो सकते थे। वह निचले क्रम में भी बल्ले से योगदान देने में सक्षम है। इसके साथ ही हरफनमौला वाशिंगटन सुंदर भी मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या से जूझ रहे हैं।

हेजलवुड टी20 विश्व कप से बाहर हुए: सीए

सिडनी (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलियाई टीम को टी20 विश्वकप से पहले ही करारा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड फिट नहीं होने के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गये हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के अनुसार हेजलवुड को टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण बाहर कर दिया गया है। हेजलवुड को एशेज सीरीज शुरू होने से पहले ही शेफील्ड शील्ड के अंतिम मैच में हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था। इसी वजह से वह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल सके। रिकवरी के दौरान उन्हें एड़ी में भी समस्या हो गई, जिससे उनकी वापसी अभी संभव नहीं है। हेजलवुड पिछले साल 12 नवंबर के बाद से से ही मैदान से बाहर हैं। इसके बाद भी उन्हें विश्व कप तक फिट होने की उम्मीद में टीम में शामिल किया गया था हालांकि वह टीम के साथ श्रीलंका नहीं गये थे। वहीं अब चयनकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें पूरी

तरह से फिट होने में समय लगेगा।

चयनकर्ता टोनी डोडमाइड ने कहा, हमें उम्मीद थी कि जोश सुपर-8 स्टेज तक मैच फिटनेस हासिल कर लेंगे पर इसमें उन्हें अभी कुछ समय लगेगा। अभी अगर उन्हें उतारा जाये तो ये नुकसानदेह होगा।

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हालांकि अभी हेजलवुड की जगह किसी नए खिलाड़ी के नाम की घोषणा नहीं की है। चयनकर्ताओं का कहना है कि शुरुआती मैचों के लिए टीम संतुलित है और आगे टूर्नामेंट की जरूरत और हालातों के हिसाब से फैसला होगा। हेजलवुड टी20 के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उना रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। उन्होंने 2021 में यूएई में हुए टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 रन देकर 3 विकेट लिए थे। उन्होंने 20.44 की औसत और 7.57 की इकॉनमी रेट से 133 विकेट लिए हैं। ऐसे में उनकी कमी पूरी करना संभव नहीं होगा।

हेजलवुड के अलावा तेज गेंदबाज पैट कमिंस भी चोटिल हैं। ऐसे में युवा ज़ेवियर बार्टलेट और बेन ड्वार्शुइस को टीम में रखा गया है। इसके अलावा ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर सीन एबॉट शामिल किये गये हैं जो हेजलवुड की जगह ले सकते हैं।

वहीं अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो नाथन एलिस और टिम डेविड ग्रुप चरण के लिए शामिल रहेंगे। ये दोनो भी हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझ रहे थे। वहीं स्पिनर एडम ज़म्पा के भी अगले सप्ताह कोलंबो में होने वाले पहले मैच से पहले फिट होने की संभावनाएं हैं। विश्वकप में टीम की कप्तानी मिचेल मार्श संभाल रहे हैं।

चीन से हारकर भारतीय महिला टीम बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप से बाहर

किंगदाओ (एजेंसी)। पिछली चैम्पियन भारतीय महिला टीम बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को दूसरे दर्जे की चीन की टीम से 0-3 से हारकर बाहर हो गई। भारत ने 2024 में इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था लेकिन इस बार पी वी सिंधू के नहीं खेलने से भारत की संभावनाओं को धक्का लगा। टूर्नामेंट में इससे पहले दो मैच जीत चुकी दुनिया की 42वें नंबर की खिलाड़ी तन्वी शर्मा दसवीं रैंकिंग वाली गाओ फांग जिसे एकतरफा मुकाबले में 9-21, 9-21 से हार गई। गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली की जोड़ी ने जुझारू खेल दिखाया लेकिन दुनिया की चौथे नंबर की जोड़ी जिया यि फान और झांग शू शियान से 22-24, 18-21 से पराजय का सामना करना पड़ा। रक्षिता रामराज दूसरे एकल में शू वेन जिंग से 70 मिनट के मुकाबले में 14-21, 21-15, 17-21 से हार गई। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में म्यामांर को 5-0 से हराया था लेकिन थाईलैंड से 2-3 से हार गई थी। भारतीय पुरूष टीम क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी।

नेपाल के दीपेंद्र के नाम है टी20 में सबसे तेज अर्धशतक का रिकार्ड

मुम्बई। आईसीसी टी20 विश्वकप में रोहित पौडेल की कप्तानी में नेपाल की टीम उतरेगी। नेपाल को विश्व कप लिए ग्रुप-सी में रखा गया है। इस ग्रुप में इटली, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड की टीमें शामिल है। नेपाली टीम अपने चारों लीग मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी। उसका शुरुआती मुकाबला 8 फरवरी को इंग्लैंड से होना है। इसके बाद उसे इटली, वेस्टइंडीज का मुकाबला करना है। नेपाल की टीम के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक का रिकार्ड दीपेंद्र के नाम है। दीपेंद्र ने हांगझोउ एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में केवल 9 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। जो इस बार भी टूटना असंभव है। दाएं हाथ के बैटर दीपेंद्र के नाम टी20 मैच के दौरान एक ओवर में छह छक्के जड़ने का भी रिकार्ड है। टी20 अंतरराष्ट्रीय में नेपाल की ओर से सबसे अधिक रनों का रिकार्ड भी इस खिलाड़ी के नाम है। दीपेंद्र ने 90 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 32.06 के औसत से 1956 रन बनाये हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 10 अर्धशतक बनाये। इनके बाद कुशल भुरतेल और आसिफ शेख हैं, जिन्होंने अबतक 70 और 68 मैचों में क्रमशः 1807 एवं 1639 रन बनाए हैं।

मंगोलिया के खिलाफ उस मुकाबले में नेपाल ने तीन विकेट पर 314 रन बनाए थे, जो तब टी20 अंतरराष्ट्रीय का सबसे बड़ा स्कोर था हालांकि जिम्बाब्वे ने अक्टूबर 2024 में गाम्बिया के खिलाफ 344/4 का स्कोर बनाकर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था। गेंदबाजों की बात करें तो स्पिनर संदीप लामिछाने टी20 इंटरनेशनल में नेपाल के सबसे सफल गेंदबाज हैं। संदीप ने 67 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 12.05 की औसत से 129 विकेट लिए है। नेपाली टीम ने अब तक 112 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 65 में जीत हासिल की जबकि 41 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। नेपाल की टीम टी20 में वेस्टइंडीज, आयरलैंड और नीदरलैंड्स को भी हरा चुकी है!

टी20 विश्व कप के लिए अंपायिंग पैनल में रहेंगे गावस्कर, शास्त्री, सहित कई दिग्गज

दुबई। भारत और श्रीलंका में शनिवार से शुरु हो रहे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए कमेंट्री पैनल की घोषणा कर दी गयी है। इसमें भारत से सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक और हर्षा भोगले रहेंगे। इसके अलावा कमेंट्री पैनल में ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच, श्रीलंका के कुमार संगकारा, एंजेलो मैथ्यूज, वेस्टइंडीज के सैमुअल बद्री और कार्लोस ब्रेथवेट के अलावा दक्षिण अफ्रीका के टेंबा बावुमा रहेंगे। इस टूर्नामेंट में कुल 55 मैच खेले जाएंगे और इन सभी मुकाबलों में यही कमेंटेटर रहेंगे। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करने के इरादे से उतरेगी। उसका लक्ष्य तीसरी बार टी20 विश्व कप जीतने के साथ-साथ खिताब को बरकरार रखना है। भारतीय टीम को टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अक्टूबर 2023 के बाद से ही भारतीय टीम ने अपने पिछले 56 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से 48 में जीत दर्ज की थी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पहले ही दिन 7 फरवरी को करेगी। ग्रुप स्तर में उसका पहला मुकाबला अमेरिका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

कमेंटेटरों की पूरी सूची इस प्रकार है-

रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, इयान स्मिथ, इयान बिशप, आरोन फिंच, दिनेश कार्तिक, कुमार संगकारा, सैमुअल बद्री, रॉबिन उथप्पा, कार्लोस ब्रेथवेट, इयोन मॉर्गन, वसीम अकरम, सुनील गावस्कर, मैथ्यू हेडन, रमीज राजा, डेल स्टेन, माइकल एथरटन, वकार यूनिस, साइमन डूल, शॉन पोलॉक, केटी मार्टिन, हर्षा भोगले, म्पुमेलेलो मबांगवा, नताली जर्मनोस, डैनी मॉरिसन, एलन विल्किंस, इयान वार्ड, मार्क हॉवर्ड, निक नाइट, अथर अली खान, कैस नायडू, बाजिद खान, रौनक कपूर, नायल ओब्रायन, प्रेस्टन मॉमसेन, एंड्रयू लियोनार्ड, रसेल अर्नोल्ड, रोशन अबेसिंघे, एंजेलो मैथ्यूज और टेम्बा बावुमा।

जरूरत पड़ी तो टी20 विश्व कप में भारत दो स्पिनरों को खिलाएगा: सूर्यकुमार यादव

मुंबई (एजेंसी)। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत टी20 विश्व कप में दो स्पिनरों को खिलाने से संकोच नहीं करेगा। उन्होंने साथ ही वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को लेकर चयन की उलझन को 'बहुत अच्छा सिरदर्द' बताया। कुलदीप और वरुण दोनों ने टी20 विश्व कप से पहले भारत की अंतिम श्रृंखला में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की टी20 सीरीज में हिस्सा लिया था। लेकिन दोनों को एक साथ केवल रायपुर में हुए दूसरे टी20 मैच में ही मौका मिला जिसमें भारत ने सात विकेट से जीत दर्ज की।

अमेरिका के खिलाफ टी20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले से पहले मीडिया से बात करते हुए सूर्यकुमार ने कहा, 'यह एक अतिरिक्त फायदा है कि आपके पास इतने अच्छे गेंदबाज उपलब्ध हैं। लेकिन साथ ही आपको टीम संयोजन भी देखना होता है कि किस प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ किसे खिलाया जाए।' भारतीय कप्तान ने कहा, 'अगर जरूरत होगी कि हम दो स्पिनर या दो कलाई के स्पिनर को खिला सकते हैं तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव जैसे विकल्प होना हमेशा अच्छा होता है। ये दुनिया के बेहतरीन स्पिनरों में से हैं और यह एक बहुत अच्छा सरदर्द है।'

सूर्यकुमार ने यह भी कहा कि टीम के पास दाएं हाथ के बल्लेबाजों की तुलना में बाएं हाथ के बल्लेबाज ज्यादा होना भी एक अच्छी परेशानी है। ईशान किशन के अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय है तो सूर्यकुमार ने जवाब दिया, 'क्या आप चौके-छक्के लगते हुए देखना पसंद नहीं करते?'

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह एक अच्छी परेशानी है और इस पर जरूरत से ज्यादा बातचीत की जा रही है। इस स्तर पर जब आप बाएं हाथ के स्पिनरों या ऑफ स्पिनरों के खिलाफ काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, आप इतना क्रिकेट खेल चुके हैं और इतना अभ्यास कर चुके हैं।' उन्होंने कहा, 'किसी भी दिन, चाहे स्पिनर गेंदबाजी कर रहा हो या तेज गेंदबाज और चाहे सामने दो बाएं हाथ के बल्लेबाज हों या दो दाएं हाथ के बल्लेबाज, आपका काम वही करना होता है जो टीम के लिए सबसे बेहतर हो और ऐसा ही हो रहा है।'

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

ट्रम्प पर हमले की कोशिश करने वाले शख्स को उम्रकैद

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के फ्लोरिडा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हत्या की कोशिश के मामले में दोषी ठहराए गए रयान राउथ को फेडरल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, सजा बुधवार (स्थानीय समय) को सुनाई गई। यह घटना 15 सितंबर 2024 को हुई थी, जब ट्रम्प राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। राउथ एके-47 जैसी सोवियत शैली की राइफल और बॉडी आर्मर के साथ ट्रम्प के गोल्फ कोर्स के पास झाड़ी में पास छिपा था। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने राइफल की नली और आरोपी का चेहरा देखा और गोली चलाई, जिसके बाद राउथ मौके से भाग गया। बाद में उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। अदालत ने रयान राउथ को सितंबर 2024 में पांच आरोपों में दोषी ठहराया था। इनमें घटना के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रम्प की हत्या की कोशिश का मामला भी शामिल है। यह फैसला अमेरिकी जिला जज एलीन कैनन ने सुनाया। अदालत की कार्यवाही के दौरान जज कैनन ने कहा कि आरोपी ने रयान का इरादा साफ तौर पर ट्रम्प की हत्या करना था और अपने मंसूबे को अंजाम देने के बेहद करीब पहुंच गया था। उम्रकैद के अलावा राउथ को कई अन्य सजाएं भी दी गईं, जो साथ-साथ चलेंगी। इनमें हिंसक अपराध के दौरान हथियार रखने पर 84 महीने, एक फेडरल अधिकारी पर हमला करने के लिए 240 महीने, सजायाफ्ता अपराधी होने के बावजूद हथियार रखने पर 18 महीने और सीरियल नंबर मिटे हथियार के कब्जे के लिए 60 महीने की सजा शामिल है।

जमात-ए-इस्लामी के बदले तेवर, चुनावी घोषणापत्र में भारत से अच्छे रिश्तों का वादा

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में इसी महीने 12 फरवरी को चुनाव हैं। ऐसे में देश के अंदर प्रमुख राजनीतिक दल जमात-ए इस्लामी एक अहम ताकत के रूप में उभरती नजर आ रही है। भारत विरोधी गुट के रूप में पहचान जाने वाले जमात ने अपना बुधवार (04 फरवरी) को घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने भारत के साथ अच्छे रिश्तों पर जोर दिया। बांग्लादेश की प्रमुख इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने चुनावों से पहले 41 सूत्रीय घोषणापत्र जारी किया, जिसमें न्याय और आर्थिक क्षेत्रों में सुधारों के साथ-साथ मंत्रिमंडल में महिलाओं को शामिल करने का वादा किया गया है। जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान ने घोषणापत्र जारी किया, जिसमें पार्टी के सत्ता में आने पर 'राजकब्जा में पर्याप्त संख्या में महिलाओं को शामिल करने' का वादा किया गया।, हालांकि पार्टी ने कोई भी महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतार है। इस्लामिक कंजर्वेटिव पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने अपने घोषणापत्र में भारत सहित पड़ोसी देशों के साथ रचनात्मक और सहयोगात्मक रिश्ते बनाए रखने का वादा किया है। पार्टी के बयान के अनुसार ये संबंध आपसी सम्मान और निष्पक्षता के आधारित होंगे। घोषणापत्र में दावा किया गया कि भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव और थाइलैंड के साथ शांतिपूर्ण, मित्रतापूर्ण और सहयोगी संबंध स्थापित किए जाएंगे। पार्टी ने जोर दिया कि क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के लिए पड़ोसियों के साथ संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।

ईरानी ड्रोन से रूस की ताकत में इजाफा, यूक्रेन की बढ़ी चिंता

कीव, एजेंसी। यूक्रेन में जमीनी मोर्चे पर लंबी और थकाऊ जंग के बीच रूस अब आसमान में बढ़त बनाने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। इस रणनीति की धुरी हैं लंबी दूरी तक मार करने वाले, कम लागत वाले और लगातार उन्नत हो रहे ड्रोन जिनके विकास, डिजाइन और उत्पादन में ईरान की निर्णायक भूमिका सामने आ रही है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के अनुसार ईरानी तकनीकी सहयोग के दम पर रूस जल्द ही प्रतिदिन करीब 1,000 ड्रोन बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। इससे युद्ध का संतुलन और अधिक जटिल होता जा रहा है। अमेरिकी अकादमिक न्यूज प्लेटफॉर्म द कन्वर्सेशन और अल जजीरा की रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी की शुरुआत में यूक्रेन में गिरे एक ड्रोन के मलबे ने संकेत दिया कि रूस युद्ध में एक नए, तेज गति वाले ड्रोन मॉडल को उतार चुका है। यूक्रेनी खुफिया आकलन के मुताबिक रूस भी जल्द इसी स्तर का उत्पादन हासिल कर सकता है, जिसमें ईरान का तकनीकी सहयोग केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। यूक्रेन की मुख्य चिंता रूस द्वारा लंबी दूरी के अटैक ड्रोन के बढ़ते उत्पादन को लेकर है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2022 में संघर्ष शुरू होने के समय रूस बड़ी संख्या में कामिकाजे ड्रोन बनाने में सक्षम नहीं था। उसकी सैन्य सोच पारंपरिक हथियारों और मिसाइलों पर केंद्रित थी, जबकि ड्रोन को मुख्य रूप से निगरानी, टोही और खुफिया कार्यों तक सीमित माना गया। निर्णायक मोड़ तब आया जब मॉस्को ने समझा कि लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन युद्ध की दिशा बदल सकते हैं।

समंदर में 4 घंटे तैरता रहा 13 साल का बच्चा:मां और भाई-बहन की जान बचाई

पर्थ, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया में 13 साल के एक बच्चे ऑस्टिन एपलबी ने समुद्र में करीब 4 घंटे तैरकर अपनी मां और दो छोटे भाई-बहनों की जान बचाई। वह परिवार के साथ समुद्र में गया था। अचानक लहरें तेज हो गईं। बोट पलटने से सभी बहते हुए समुद्र में 14 किमी दूर निकल गए थे। द गॉर्जियन के मुताबिक, जोआन एपलबे अपने बच्चों ऑस्टिन, ब्यू और ग्रेस के साथ पर्थ से करीब 200 किलोमीटर दूर क्विंडलप में छुट्टियां मना रही थीं। शुक्रवार दोपहर वे समुद्र के किनारे पैडलबोर्ड के साथ पानी में खेल रहे थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बच्चे थोड़ा दूर चले गए और तभी तेज हवा चलने लगी। हवा के कारण उनके चप्पू गिर गए और वे सभी धीरे-धीरे समुद्र में बहने लगे। हालात बहुत जल्दी खराब हो गए। जोआन को लगा कि अब किसी को मदद लाने के लिए किनारे जाना होगा। उन्होंने अपने 13 साल के बेटे ऑस्टिन को चुना, क्योंकि उन्हें लगा वही सबसे मजबूत है।

किनारे पर पहुंचते ही ऑस्टिन ने 2 किमी दौड़ लगाई : ऑस्टिन समुद्र में तैरकर मदद लाने निकल पड़ा। उसने अपनी लाइफ जैकेट भी उतार दी क्योंकि वह मदद नहीं कर रही थी। अगले दो घंटे तक वे डर के बावजूद प्रार्थना करते रहे, गाने गुनगुनाते रहे और अच्छी बातें सोचते रहे। ऑस्टिन ने कहा कि वे अपनी मां, भाई, बहन, दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे थे।

तूफान में बोट पलटने से 14किमी दूर बहा परिवार

जब उनके पैर जमीन से टकराए, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वे किनारे पहुंच गए हैं। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि उनका परिवार अभी भी समुद्र में हो सकता है। शाम करीब छह बजे वे किनारे पहुंचे और 2 किमी दौड़कर अपनी मां के बैग तक पहुंचे वहां, उसने फोन मिलने पर रेस्क्यू टीम से मदद मांगी। इसके बाद पुलिस ने बड़े स्तर पर तलाश शुरू की। फोन करने के बाद वह थकान से बेहोश हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। उस समय उसे नहीं पता था कि उसकी मां और भाई-बहन जिंदा हैं या नहीं।

मां को लगा की ऑस्टिन नहीं बचा : वहीं दूसरी तरफ ऑस्टिन के परिवार को लगा कि किनारा ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे ऑस्टिन आगे बढ़ता गया, मां और बाकी बच्चे और दूर समुद्र में बहते चले गए। कुछ ही देर में वे ऑस्टिन को देख भी नहीं पा रहे थे। अंधेरा हो गया और लहरें तेज होती चली गईं। मां और बच्चे लाइफ जैकेट पहने पैडलबोर्ड को पकड़कर किसी तरह खुद को संभाले हुए थे। जोआन को लगने लगा कि शायद ऑस्टिन समय पर नहीं पहुंच पाएगा। समुद्र में मां और बच्चे अंधेरे, ठंड और ऊंची लहरों के बीच फंसे हुए थे। जोआन ने बताया कि उन्हें लगने लगा था कि ऑस्टिन शायद नहीं बचा और अब कोई मदद नहीं आने वाली है।

रेस्क्यू से पहले बच्चे पानी में गिर गए थे : काफी देर बाद बचाव दल ने परिवार को समुद्र में करीब 14 किलोमीटर दूर ढूंढ लिया। उस समय एक बड़ी लहर में बच्चे पानी में गिर गए थे। जोआन ने ग्रेस की चीख सुनी, लेकिन ब्यू की आवाज नहीं आ रही थी। बाद में बचावकर्मियों ने उसे भी ढूंढ लिया। अस्पताल में उन्होंने अपने पिता को फोन किया और रोते हुए बात की। उन्हें तब तक नहीं पता था कि उनकी मां और भाई-बहन जिंदा हैं या नहीं। जब ऑस्टिन को बताया गया कि उसकी मां और भाई-बहन सुरक्षित मिल गए हैं, तो वहां मौजूद डॉक्टर और पुलिस खुशी से झूम उठे। ऑस्टिन ने कहा कि वह खुद को हीरो नहीं मानता और उसने बस वही किया जो करना जरूरी था। पुलिस ने कहा कि इस 13 साल के बच्चे की हिम्मत और हौसले की वजह से उसकी मां और भाई-बहनों की जान बच सकी।

पुलिस बोली- समुद्र का मिजाज बहुत तेजी से बदलता है : पुलिस अधिकारी जेम्स ब्रैडली ने कहा कि यह घटना बताती है कि समुद्र का मिजाज कितनी जल्दी बदल सकता है। उन्होंने बताया कि मां और दोनों बच्चे लाइफ जैकेट पहने हुए थे, जिसकी वजह से वे जिंदा बच पाए। पुलिस के मुताबिक, सभी को पहले पैरामेडिक्स ने जांच की और फिर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। बाद में परिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

अमेरिकी कोर्ट का फैसला, ओरेगन में बिना वारंट अप्रवासी को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे आईसीई एजेंट

वॉशिंगटन, एजेंसी। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड में एक फेडरल जज ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, ओरेगन में अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंटों को बिना वारंट के अप्रवासी लोगों को गिरफ्तार करना बंद करना होगा, जब तक कि उनके भागने की संभावना न हो।

कोर्ट ने लगाई रोक : अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज मुस्तफा कसुभाई ने इस मामले में शुरुआती रोक लगा दी है। यह फैसला एक प्रस्तावित क्लास-एक्शन मुकदमे के बाद आया है। यह मुकदमा होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के उस तरीके के खिलाफ था, जिसमें वे अप्रवासी को देखते ही पकड़ लेते थे। आलोचकों ने इसे 'पहले गिरफ्तार करो, बाद में सही ठहराओ' वाली नीति बताया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े पैमाने पर लोगों को देश से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच इमिग्रेशन एजेंट बिना कोर्ट वारंट के निजी घरों में घुस रहे हैं। इन कार्रवाइयों ने देश भर के नागरिक अधिकार समूहों की चिंता बढ़ा दी है।

बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं : पिछले हफ्ते इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) के एक्टिंग हेड टॉड लियोन्स ने इस बात पर जोर दिया गया था कि एजेंटों को अपने अधिकारियों से जारी वारंट के बिना गिरफ्तारी

नहीं करनी चाहिए, जब तक कि व्यक्ति के भागने का ठोस कारण न हो। इस मामले में जज के सामने सबूत पेश किए गए कि ओरेगन में एजेंटों ने छापों के दौरान बिना वारंट या बिना जांच किए लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक वादी, विक्टर क्रूज गेमज की गवाही भी शामिल है।

विक्टर 56 साल के हैं और 1999 से अमेरिका में रह रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके पास काम करने का वैध परमिट था और वीजा की अर्जी भी पेंडिंग थी। इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया और तीन हफ्ते तक हिरासत केंद्र में रखा गया।

कोर्ट ने एजेंटों की हरकतों को बताया हिंसक और क्रूर : जज कसुभाई ने कहा कि ओरेगन में एजेंटों की हरकतें हिंसक और क्रूर रही हैं। उन्होंने बताया कि सिविल इमिग्रेशन उल्लंघन के लिए लोगों को हिरासत में लेते समय उन पर बंदूकें तानी गईं, जोकि गलत है। साथ ही जज ने चिंता जताई कि प्रशासन इमिग्रेशन छापों में पकड़े गए लोगों को उचित कानूनी प्रक्रिया से वंचित कर रहा है।

रूस गैरकानूनी तरीके से पावर ग्रिड को बना रहा निशाना', यूक्रेन का मॉस्को पर आरोप

कीव, एजेंसी। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन के उर्जा ठिकानों पर हमले किए हैं। जिसके बाद यूक्रेन ने भी आरोप लगाया है कि रूसी मिसाइलें और ड्रोन गैरकानूनी तरीके से उनके उर्जा ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन का आरोप है कि उनके ऊर्जा ठिकानों, पावर ग्रिड पर हमले के चलते देश की अब तक की सबसे ठंडी सर्दियों में से एक में लोग अंधेरे और ठंड में रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा, 'सर्दियों के सबसे ठंडे दिनों का फायदा उठाकर लोगों को डराना रूस के लिए कूटनीति से ज्यादा जरूरी है।' वहीं रूस का कहना है कि उसके हमले सैन्य अभियान का एक वैध हिस्सा हैं। तो क्या युद्ध के दौरान ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले की अनुमति है? आइए जानते हैं क्या कहता है सिएरा लियोन के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष न्यायालय के पूर्व मुख्य अभियोजक डेविड क्रेन ने बताया कि युद्ध के दौरान पक्ष कानूनी रूप से पावर ग्रिड को निशाना बना सकते हैं, लेकिन हमला सीधे तौर पर एक वैध सैन्य लक्ष्य को प्रभावित करने वाला

होना चाहिए और इसमें ज्यादा नागरिक हताहत नहीं होने चाहिए।

रूस ने कानून के उल्लंघन की बात नकारी : रूसी सेना ने बार-बार कहा है कि उसने एनर्जी सुविधाओं और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है जो यूक्रेनी सैन्य उद्योग और सशस्त्र बलों को समर्थन करते हैं। साथ ही रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से इनकार किया है। रूस ने कहा, 'हमारी सेना उन ठिकानों पर हमला कर रही है, जो यूक्रेन सरकार के सैन्य परिसरों से जुड़े हैं, ऑपरेशन जारी है।' वहीं कीव का आरोप है कि रूस अंधेरे, ठंडे घरों में रहने को मजबूर आम नागरिकों पर भारी मुश्किलों का बोझ डालकर यूक्रेनियन लोगों का लड़ने का हौसला तोड़ना चाहता है।

अमेरिकी कानून का सामना कर रहे मादुरो की बढ़ी मुश्किलें

वाशिंगटन, एजेंसी। अर्जेंटीना के एक जज ने बुधवार को अमेरिका से वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सौंपने की औपचारिक मांग की है। फिलहाल वह न्यूयॉर्क की एक जेल में बंद हैं और उन पर नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी सेना ने एक विशेष ऑपरेशन में पिछले महीने मादुरो को पकड़ा था।

मादुरो पर लगे हैं कई गंभीर आरोप : मामले में अर्जेंटीना के संघीय जज ने एक वारंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस काराकास में मादुरो पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने शासन के दौरान प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा करवाई। इसमें लोगों को प्रताड़ित करना और जबरन गायब करना शामिल है।

मामलों में नागरिकों को बनाया गया है वादी : इस

मामलों में उन वेनेजुएला के नागरिकों को वादी बनाया गया है जिन्होंने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंटों के हाथों भयानक यातनाएं झेली हैं। यह कानूनी लड़ाई साल 2023 में ब्यूनस आयर्स में मानवाधिकार संगठनों ने शुरू की थी। यहां की अदालतें पहले भी देश के बाहर मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच करती रही हैं। तीन जनवरी को अमेरिकी सेना ने मादुरो को सत्ता से हटाया था, जिसके बाद अर्जेंटीना के सरकारी वकीलों ने जज रामोस से इस प्रत्यर्पण अनुरोध को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था।

अमेरिका में इस मामले में चल रहा केस : अर्जेंटीना ने 1997 की प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए यह मांग की है। हालांकि, इसकी संभावना कम है कि ट्रंप प्रशासन इस पर तुरंत अमल करेगा। इसका मुख्य कारण अमेरिका में मादुरो पर चल रहा मुकदमा है। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोर्स अभी ब्रुकलिन की जेल में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 25 वर्षों तक ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर अमेरिका में हजारों टन ड्रग भेजने में मदद की।

क्या है राजनीतिक समीकरण : राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली खुद को डोनाल्ड ट्रंप का करीबी सहयोगी मानते हैं और उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी का स्वागत किया था। मानवाधिकार संगठनों ने इस प्रत्यर्पण अनुरोध को ऐतिहासिक बताया है। 'अर्जेंटीना फोरम फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी' ने कहा कि यह उन पीड़ितों की जीत है जिन्होंने ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई। अब अर्जेंटीना का विदेश मंत्रालय यह आधिकारिक अनुरोध वाशिंगटन डीसी भेजेगा, जहां अमेरिकी कानूनी विभाग इस पर विचार करेगा।

अमेरिका में टैक्सी चलाने को मजबूर पाकिस्तान के पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम खान

वाशिंगटन, एजेंसी। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी इन दिनों गुजर-बसर करने के लिए अमेरिका में टैक्सी चलाने को मजबूर हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) अमेरिका द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सरकार द्वारा उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त किए जाने के बाद वह अब अमेरिका में ड्राइविंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां ड्राइवर के रूप में काम करते हुए मुझे वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ईमानदारी से जीविका कमाने पर मुझे गर्व है।

जारी वीडियो में बताया गया है कि कासिम खान सूरी को पाकिस्तान के पूर्व

प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थन करने के कारण दजर्नों फर्जी मामलों में फंसा दिया गया। उनकी संपत्ति और बैंक खातों की जब्ती कर ली गई। साथ ही पाकिस्तान से जबरन खदेड़ दिया गया।

लोगों के लिए खड़े होने पर कीमत चुकाई : कासिम खान ने कहा कि यह वह कीमत है जो कई लोगों ने केवल इमरान खान के साथ लोकतंत्र, कानून के शासन और पाकिस्तान के लोगों के सम्मान के लिए खड़े होने के कारण चुकाई है। सूरी ने इमरान खान के खिलाफ चल रहे फर्जी अदालती मामलों पर चिंता जताई।

सूरी ने आगे कहा कि मौजूदा पाकिस्तानी सरकार का अन्याय और कुकर्म सबके सामने है। उन्होंने बताया कि सभी पाकिस्तानी इस अन्याय के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोगों को जबरिया झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।

सादगी और गरिमामय तरीके से जिया जीवन : पुराने वक्त को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय उन्होंने इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीडीए) में एक महत्वपूर्ण पद संभाला था लेकिन इससे कभी कोई निजी संपत्ति अर्जित नहीं की। उन्होंने कहा मैंने अपना जीवन गरिमा और सादगी से जिया। सूरी ने बताया कि वर्ष 2018 से पहले वह क्वेटा स्थित अपने घर पर इमरान खान और आरिफ अल्वी जैसे वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों की मेजबानी करने में सक्षम थे।

सूरी ने 15 अगस्त 2018 से 16 अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के 19वें उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह अगस्त 2018 से जनवरी 2023 तक पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने 2022 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के उप-अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

इमरान खान के बेटे को पाकिस्तान आने ही नहीं दे रही शरीफ सरकार

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान में बीते 2 साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों ने शहबाज शरीफ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरान खान के बेटे कासिम ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी अधिकारी जानबूझकर उनके और उनके भाई के वीजा प्रोसेस में देरी कर रहे हैं ताकि वे पाकिस्तान ना आ पाएं। कासिम के आरोप हैं कि उन्हें अपने पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले इमरान खान के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट की खबरें सामने आई थीं।

बता दें कि कासिम और उनके बड़े भाई सुलेमान फिलहाल अपनी मां जेमिमा गोल्डस्मिथ के साथ लंदन में रहते हैं। बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, कासिम ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'मैं और मेरा भाई अपने पिता से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं। 914 दिनों से उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है, जबकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन्हें सही चिकित्सा देखभाल से भी वंचित किया जा रहा है।

कासिम ने कहा है कि सरकार जानबूझकर उनके वीजा को प्रोसेस नहीं कर रही है। उन्होंने लिखा, 'एक कैदी को इलाज से वंचित करना क्रूरता है। बच्चों को अपने पिता से मिलने के अधिकार से वंचित करना सजा है।' कासिम ने अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की अपील करते हुए लिखा, 'मैं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और सरकारों से अपील करता हूं कि इससे पहले कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएं, आवाज उठाएं और कार्रवाई करें।'

इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की खबरें : डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों इमरान खान की सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया था। इसके बाद उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने गुपचुप तरीके से इमरान खान को बनी गाला में ट्रांसफर करने की कड़ी निंदा की थी।

पार्टी ने अधिकारियों पर उनके परिवार और पार्टी को सूचित ना करने और उन्हें निजी डॉक्टरों तक पहुंच से वंचित करने का आरोप लगाया। इस बीच नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता महमूद खान अचकजई ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक चिट्ठी लिखकर इमरान खान की मेडिकल जांच की इजाजत देने का भी अनुरोध किया।

अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय गिरोह से जुड़े 200 से अधिक अवैध ऑनलाइन फार्मेसी डोमेन जब्त किए

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका ने ऑनलाइन फार्मेसियों से जुड़े भारत-आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन (टीसीओ) की 200 वेबसाइट के डोमेन को जब्त कर लिया है। अमेरिका के ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (डीईए) ने यह कार्रवाई की। डीईए के अनुसार, यह संगठन अमेरिका में काम कर रहा है और कथित तौर पर कम से कम छह जानलेवा और चार ओवरडोज के मामलों के लिए जिम्मेदार था। 27 जनवरी से शुरू होकर पूरे अमेरिका में डीईए अधिकारियों ने कई ऑपरेशन किए और चार लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही, पांच तत्काल निलंबन आदेश और एक कारण बताओ नोटिस जारी किए। अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन ने कहा कि ये दोनों प्रशासनिक कार्रवाई हैं, जो डीईए रजिस्टर्ड लोगों के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के खतरों से जनता की रक्षा के लिए की जाती हैं। ये कार्रवाई प्रशासन की ओर से 200 से ज्यादा ऑनलाइन फार्मेसियों को बंद करने के अलावा थीं, जिन पर बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के सैकड़ों-हजारों डायवर्टेड फार्मास्यूटिकल्स और नकली गोलियों के ऑर्डर भरने का आरोप था।

नियंत्रित पदार्थ अधिनियम (सीएसए) के तहत, डीईए फार्मेसियों की हिरासत में नियंत्रित पदार्थ की हैंडलिंग, भंडारण और वितरण को विनियमित करता है। सीएसए में यह शर्त है कि फार्मेसियों को केवल वैध प्रिस्क्रिप्शन मिलने पर ही कंट्रोल्ड सब्सटेंस देने की अनुमति है, जो एक व्यक्तिगत प्रैक्टिशनर की ओर से अपने सामान्य पेशेवर अभ्यास के दौरान एक वैध चिकित्सा उद्देश्य के लिए जारी किया गया हो। डीईए के अनुसार, जांच में पाया गया कि इन ऑनलाइन फार्मेसियों के ऑपरेटर और उनके सह-साजिशकर्ता बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के, पूरे अमेरिका में ग्राहकों को अवैध रूप से डायवर्टेड दवाएं बेच रहे थे

और भेज रहे थे, जो सीएसए का उल्लंघन था और मरीजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए डिस्ट्रीब्यूशन के एक बंद सिस्टम में खतरनाक तरीके से घुसपैठ कर रहे थे।

इस जांच के दौरान डीईए ने हजारों ऐसे ग्राहकों की पहचान की, जिन्होंने इन ऑनलाइन फार्मेसियों के माध्यम से दवाएं खरीदी थीं। इसके बाद डीईए ने इस चल रही जांच के समर्थन में जानकारी मांगने के लिए जनता को 20 हजार से अधिक पत्र भेजे हैं।

ड्रग प्रवर्तन प्रशासन ने एक बयान में कहा कि अवैध ऑनलाइन फार्मेसियां ??अक्सर असली दिखने के लिए अमेरिकी-आधारित वेबसाइट पते और प्रोफेशनल दिखने वाले डिजाइन का इस्तेमाल करती हैं, जबकि असल में वे ऐसी नहीं होतीं। ये कंपनियां अवैध रूप से काम करती हैं, जानबूझकर अमेरिकी ग्राहकों को यह विश्वास दिलाकर धोखा देती हैं कि वे कानूनी रूप से सुरक्षित, विनियमित दवाएं खरीद रहे हैं।

बयान में आगे कहा गया, 'ऑपरेशन मेल्टडाउन के तहत बंद की गई कई साइटों ने खुद को वैध, अमेरिका-आधारित और एफडीए-अनुमोदित होने का दावा किया था, लेकिन डीईए की जांच में पता चला कि इन साइटों के ऑपरेटर अक्सर ड्रग तस्करों के साथ मिलकर ऑनलाइन ऑर्डर को नकली गोलियों या गलत तरीके से इस्तेमाल की गई दवाओं से पूरा करते थे। ये नकली दवाएं अक्सर फेंटानिल या मेथामफेटामाइन से बनी होती हैं और इन्हें लेने से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं, जिसमें हानिकारक साइड इफेक्ट, अप्रभावी इलाज और यहां तक ??कि मौत भी शामिल है।'

अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन ने बयान में यह भी कहा कि अपनी ग्लोबल पहुंच का इस्तेमाल करते हुए डीईए भारत सरकार के कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ मिलकर उन खतरनाक आपराधिक संगठनों की पहचान करने, जांच करने और उन्हें खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करता है, जो इस तरह के अवैध ड्रग तस्करी ऑपरेशन में शामिल हैं।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

जालंधर मर्डर केस पर गरमाई सियासत, सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार पर कसा तंज

चंडीगढ़ (एजेंसी)। जालंधर में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले ने पंजाब की राजनीति को गरमा दिया है। इस घटना को लेकर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला करते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुखबीर बादल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि पंजाब में अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं और हालात इतने खराब हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के अपने नेता भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी के नेता अपनी ही सरकार में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो कानून-व्यवस्था की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने जालंधर के मॉडल टाउन इलाके में गुरुद्वारा साहिब के बाहर हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता लक्की ओबराए की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं बचा है। सुखबीर बादल के मुताबिक, सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की घटना राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। अकाली दल प्रमुख ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2026 में अब तक पंजाब में करीब 25 हत्याएं हो चुकी हैं, जबकि महीने के पहले सप्ताह में ही 9 हत्याओं के मामले सामने आए थे। उन्होंने कहा कि ये वारदातें किसी एक इलाके तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे राज्य में फैल चुकी हैं। चाहे कोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, व्यस्त बाजार, शादी समारोह का स्थल हो या फिर गुरुद्वारा साहिब के बाहर—अपराध हर जगह हो रहे हैं। सुखबीर बादल ने सरकार और पुलिस द्वारा गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही सख्त कार्रवाई के दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है।

भाजपा विधायक को 'लुटेरा' कहने वाले उप्र कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर

लखनऊ (एजेंसी)। सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह को 'लुटेरा' कहने के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर की गई है। यह मामला अजय राय द्वारा एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने विधायक पर देश और प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया था। भाजपा नेता शिवशंकर सिंह उर्फ शंकरी की शिकायत पर सरोजनी नगर थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया कि 1 फरवरी 2026 को सरोजनी नगर के गौरी-बिजनौर रोड स्थित नटकुर तिराहा पर एक राजनीतिक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा को संबोधित करते हुए अजय राय ने कहा था कि विधायक राजेश्वर सिंह देश और प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में रहते हुए भी लूट-खसोट जारी रही। शिकायतकर्ता के अनुसार, अजय राय का बयान पूरी तरह असत्य, तथ्यहीन और मानहानिकारक है, जिससे विधायक की छवि को नुकसान पहुंचा है। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि भाषण को योजनाबद्ध तरीके से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। भाजपा नेता ने 'रुद्रदमन सिंह' नामक फेसबुक अकाउंट से वीडियो साझा किए जाने का आरोप लगाया है।

बिहार में नीट छात्रा की मौत का मामला : राबड़ी देवी ने पुलिस पर तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया

पटना (एजेंसी)। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की नेता राबड़ी देवी ने राज्य में नीट छात्रा की मौत के मामले में पुलिस और सरकार पर तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया है। यह घटना पिछले महीने 6 जनवरी को पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित छात्रावास में हुई थी। जहानाबाद निवासी छात्रा को अचेत अवस्था में पाया गया था और कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को उसने निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। बजट सत्र के तीसरे दिन विधानपरिषद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि राज्य में किसी भी जिले में अपराध नहीं हो रहे हैं ऐसा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और गृह मंत्री इस मामले में चुप हैं और सभी तथ्यों को छिपाने के बाद इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि अपराध में शामिल लोग सरकार का हिस्सा हैं। सीबीआई क्या करेगी? यह एजेंसी भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। इस मामले पर जनता दल यूनाइटेड के विधानपरिषद सदस्य नीरज कुमार ने राबड़ी देवी की टिप्पणियों को मीडिया में सुर्खियां बटोरने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपराधियों को कानूनी कार्रवाई से नहीं बचाती और इस तरह के आरोप निराधार हैं। परिवार ने अधिकारियों पर मामले को दबाने का आरोप लगाया था। बिहार सरकार ने मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सिफारिश की थी। फिलहाल विशेष जांच दल इस घटना की जांच कर रहा है। राबड़ी देवी ने विधानसभा में कहा कि इस बजट में बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं है और सरकार केवल जनता को गुमराह कर वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है।

रांची के जाने-माने कारोबारी और बिल्डर अनुराग सरावगी ने की आत्महत्या

रांची (एजेंसी)। रांची के जाने-माने बिल्डर और व्यवसायी अनुराग सरावगी ने मेन रोड स्थित ब्लेयर अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से न केवल इलाके में हड़कंप मच गया, बल्कि राजधानी के कारोबारी जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार अनुराग सरावगी गुरुवार रात करीब 11 बजे अपार्टमेंट में अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे कूद गए। ऊंचाई से गिरने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तेज आवाज सुनकर अपार्टमेंट के सुरक्षाकर्मी और स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर पहुंचे, जहां उनका शव पड़ा मिला। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि अनुराग गुरुवार की रात घर पर अकेले थे। उनकी पत्नी और दोनों बच्चे किसी रिश्तेदार के यहां तमिलनाडु गए हैं। अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ लोगों ने पुलिस को बताया है कि वह देर रात किसी से मोबाइल पर ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदपीढ़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी, कोतवाली डीएसपी समेत वरीय पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे।

सरकारी जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, एयर इंडिया के 70 फीसदी विमानों में तकनीकी खराबी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की प्रमुख विमानन कंपनी एयर इंडिया के बेड़े को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि एयरलाइन के हर 10 में से 7 विमानों में किसी न किसी तरह की तकनीकी खामी पाई गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एयर इंडिया के लगभग 70 फीसदी विमान तकनीकी रूप से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो सभी भारतीय एयरलाइन्स में सबसे अधिक है।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2026 तक विभिन्न एयरलाइनों के कुल 377 विमानों में बार-बार गड़बड़ी होने के मामले दर्ज किए गए। सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि एयर इंडिया के जिन 166 विमानों की जांच की गई, उनमें से 137 विमानों में तकनीकी खामियां पाई गईं। इसी समूह की अन्य कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के भी 101 विमानों में से 54 में बार-बार खराबी की बात सामने आई है। जांच के दायरे में केवल एयर इंडिया ही नहीं, बल्कि अन्य निजी एयरलाइन्स भी रहीं। इंडिगो के 405 विमानों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 148 विमानों में तकनीकी समस्याएं मिलीं। वहीं, स्पाइसजेट के 43 विमानों में से 16 और अकासा एअर के 32 विमानों में से 14 विमानों में बार-बार गड़बड़ी होने की पुष्टि हुई है। इस अवधि के दौरान विमानन सुरक्षा नियामक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कुल 3,890 निगरानी निरीक्षण किए।

हालांकि, मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले तीन वर्षों में उड़ानों के दौरान तकनीकी खराबी की कुल घटनाओं में धीरे-धीरे कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में खराबी के 448 मामले सामने आए थे, जो 2024 में घटकर 421 रह गए। सरकार का दावा है कि डीजीसीए के पास हवाई अड्डा संचालकों और विमानों की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित सुरक्षा तंत्र मौजूद है, जिसके तहत औचक निरीक्षण और नियामक ऑडिट किए जाते हैं। नियमों के उल्लंघन या सुरक्षा मानकों में कोताही पाए जाने पर डीजीसीए द्वारा सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। एयरलाइन्स के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे किसी भी तकनीकी घटना की रिपोर्ट तुरंत नियामक को दें। ऑडिट के दौरान मिलने वाली कमियों को दूर करने के लिए संबंधित एयरलाइन्स को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए जाते हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र, कहा- गोवंश यदि सुरक्षित हैं इसका हो परीक्षण

वाराणसी (एजेंसी)। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गोवंश को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल ही में राज्य के पशुपालन मंत्री ने उनके द्वारा उठाए गए गोकशी के गंभीर मुद्दे को 'भ्रम' और 'असत्य' करार दिया। मंत्री ने दावा किया था कि राज्य में गो-वंश पूर्णत: सुरक्षित है। शंकराचार्य ने पत्र में कहा कि धर्मसत्ता और राजसत्ता के बीच सत्य की स्थापना के लिए आवश्यक है कि दावों का धरातलीय एवं वैज्ञानिक परीक्षण हो। यदि शासन का विश्वास अडिग है कि राज्य में गोहत्या पूर्णत: बंद हो चुकी है, तो पारदर्शिता के लिए ज्योतिषपीठ के प्रतिनिधियों को कुछ बिंदुओं पर अनुमति एवं पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। उन्होने मांग की कि निर्यातित मांस का डीएनए परीक्षण कराया जाए। हापुड़, अलीगढ़, मेरठ और उन्नाव जैसे निर्यात केंद्रों से रैंडम सैंपलिंग कर स्वतंत्र जांच की अनुमति दी जाए। चर्म शोधन इकाइयों का निरीक्षण किया जाए। कानपुर एवं अन्य क्षेत्रों में आने वाली खालों के वैज्ञानिक परीक्षण हेतु प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए। परिवहन एवं सीमा निरीक्षण किया जाए। अंतर्राज्यीय सीमाओं और प्रमुख मार्गों पर संदिग्ध वाहनों के आकस्मिक निरीक्षण में प्रशासनिक सहयोग दिया जाए। नगर निकायों एवं निजी वधशालाओं की व्यवस्था की धरातलीय जांच के लिए 'सरप्राइज ऑडिट' का अधिकार प्रदान किया जाए। इसके अलावा गौशाला एवं निस्तारण केंद्रों का ऑडिटरू सरकारी गौशालाओं में मृत्यु के कारणों एवं शवों के निस्तारण की प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराई जाए और अधिकृत प्रयोगशालाओं की सूची जारी की जाए। शंकराचार्य ने कहा कि इन बिंदुओं के तहत संकलित नमूनों की निष्पक्ष जांच के लिये शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची उपलब्ध कराई जाए, जिनकी रिपोर्ट को शासन साक्ष्य के रूप में स्वीकार करता हो। इससे भविष्य में जांच परिणामों पर कोई विवाद नहीं रहेगा।

उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी: पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में घने कोहरे का अलर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और कोहरे का दोहरा सितारा जारी है। हिमाचल प्रदेश के 14 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे दर्ज किया गया है, जिससे समूचा राज्य शीत लहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी के निचले इलाकों में दृश्यता काफी कम रहने का अनुमान है।

केवल हिमाचल ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर खत्म होते ही उत्तरी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। राज्य के ग्वालियर समेत 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है, जबकि 30 से अधिक जिलों में घना कोहरा देखा गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सुबह के समय घने कोहरे और बर्फीली हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। पहाड़ी राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 9 फरवरी से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का नया दौर शुरू हो सकता है। उत्तराखंड में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 10 और 11 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। आगामी 7 और 8 फरवरी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है, जिससे सुबह और रात की ठंड और अधिक महसूस होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही हलचल का सीधा असर मैदानी इलाकों के तापमान पर पड़ेगा, जिससे फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रशासन ने कोहरे को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने की सलाह दी है।

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा: नए उपमुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के विरोध में भारी बवाल

चुराचांदपुर (एजेंसी)। मणिपुर में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही राज्य में एक बार फिर अशांति का माहौल पैदा हो गया है। विशेष रूप से चुराचांदपुर जिले में गुरुवार को स्थिति उस समय अनियंत्रित हो गई, जब नए उपमुख्यमंत्रियों के रूप में नेमचा किपगेन और एल दिखो के शपथ ग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक संघर्ष में बदल गया। पूरे क्षेत्र में व्याप्त भारी तनाव को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं।

हिंसा की शुरुआत गुरुवार शाम करीब 6 बजे तुइबोंग मेन मार्केट इलाके में हुई। यहां सैकड़ों की संख्या में युवा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और सुरक्षा बलों को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगे। जब सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, तो भीड़ उग्र हो गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीचों-बीच टायर जलाकर आवागमन बाधित कर दिया। युवाओं का यह आक्रोश उस समय चरम पर पहुंच गया, जब उन्हें सूचना मिली कि कुकी-जोमी समुदाय के तीन विधायक सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इनमें नेमचा किपगेन ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जबकि एलएम खाउते और नगुरसंगलुर के भी सरकार में शामिल होने की खबरें हैं। स्थानीय कुकी संगठनों ने पहले ही अपने समुदाय के विधायकों को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि वे वर्तमान परिस्थितियों में सरकार में शामिल न हों। समुदाय का एक बड़ा धड़ा इस बात से आहत है कि इंफाल में हुई पिछली हिंसा के दौरान जान-माल और धार्मिक स्थलों का भारी नुकसान हुआ था, जिसकी टीस अभी भी बरकरार है। समुदाय का मानना है कि ऐसे समय में सत्ता में साझेदारी करना उनके हितों और भावनाओं के खिलाफ है। इसी नाराजगी के चलते चुराचांदपुर में विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया गया।

राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो, एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के करीब एक साल बाद राज्य में नई सरकार का उदय हुआ है। युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। उनके साथ भाजपा की नेमचा किपगेन और नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के एल दिखो ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस नई राजनीतिक व्यवस्था को क्षेत्रीय गुटों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिससे टकराव की स्थिति बनी हुई है। हालात पर काबू पाने के लिए असम राइफल्स और पुलिस के जवानों को मोर्चे पर लगाया गया है। शुरुआती झड़पों के बाद सुरक्षा बलों को कुछ समय के लिए पीछे हटना पड़ा, लेकिन भीड़ के लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए अंततः आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वर्तमान में, आदिवासी संगठन ज्वाइंट फोरम ऑफ सेवन ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूर्ण बंद का आह्वान किया है। संगठन ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई विधायक या नेता इस बंद और समुदाय की भावनाओं का उल्लंघन करता है, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सुरक्षा एजेंसियां संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही हैं ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके।

गोलवलकर से जुड़ी टिप्पणी को लेकर फंसे दिग्विजय, नहीं होगी मानहानि याचिका खारिज

-कोर्ट ने कहा कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर मानहानि याचिका में वैध कारण बनता है

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) और दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में उनके खिलाफ दायर एक मानहानि याचिका को कोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया है। 8 जुलाई 2023 को सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर की एक तस्वीर साझा करके उसके कैप्शन में लोगों से सवाल पूछा था कि क्या वह दलितों, पिछड़े वर्गों, मुसलमानों और भूमि, जल व जंगल से जुड़े मुद्दों पर गोलवलकर के विचारों से परिचित हैं?

इस पोस्ट को लेकर संघ के स्वयंसेवक शशिकांत चंपानेकर ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे संघ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। याचिका के दाखिल होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। राज्यसभा सांसद सिंह ने इस याचिका को खारिज करने की अपील करते हुए तर्क दिया कि यह मामला कानूनन विचारणीय नहीं है। इस पर सिविल जज राजेश बी. खंडारे ने कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि याचिका में वैध कारण बनता है। इसी वजह से इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह की ओर से दलील दी गई कि याचिका कर्ता को यह मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि संघ न तो कोई पंजीकृत संस्था है और न ही कानूनी व्यक्ति है। ऐसे में वह मुकदमा दायर नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर कोई व्यक्तिगत सदस्य संघ और गोलवलकर की ओर से हर्जाना कैसे मांग सकता है?

इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आपराधिक मानहानि कानून के तहत किसी पहचाने जाने योग्य समूह की मानहानि की जा सकती है और उस समूह का कोई आहत सदस्य कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े गंभीर और विचारणीय मुद्दे हैं, जिनका फैसला केवल साक्ष्य दर्ज होने के बाद ही किया जा सकता है, न कि वाद खारिज करने के चरण पर। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस वाद को खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कारण बनता है, संघ सदस्य के मुकदमा दायर करने के अधिकार को इस चरण पर कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं कहा जा सकता और वाद के मूल्यांकन या कोर्ट फीस की पर्याप्तता जैसे मुद्दे बिना सुधार का अवसर दिए वाद खारिज करने का आधार नहीं बन सकते।

कोयला खदान में विस्फोट से अब तक 18 की मौत, कई मलबे में दबे, बचाव कार्य जारी

-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने जताया दु:ख, मृतकों के परिवारों को सहायता की घोषणा

शिलांग (एजेंसी)। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को कोयला खदान में विस्फोट ने पूरे देश को हिला दिया। अवैध रूप से संचालित इस खदान में अचानक हुए धमाके के बाद चीख-पुकार मच गई। मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। विस्फोट इतना भीषण था कि कई मजदूर अंदर ही फंस गए। राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंची। भारी मशक्कत के बाद 18 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं, कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे ने खदानों में सुरक्षा व्यवस्था और अवैध खनन के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। हादसे की खबर मिलते ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सक्रिय हो गईं। पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। वहीं मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक शुरआती जांच में सामने आया है कि यह खदान अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक विस्फोट खदान के अंदर हुआ, जिससे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। प्रशासन ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता, खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और विशेष टीमों को लगाया गया है।

हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी घटना की जांच और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम संगमा से बातचीत कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा मेघालय सरकार ने मृतकों के परिवारों को तीन-तीन लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि यह मदद पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए दी जा रही है। हादसे के बाद लोगों में गुस्सा है।

सीएम कॉनराड संगमा ने कहा है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। प्रशासन ने साफ किया है कि राज्य में वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा दिया जाएगा और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, अगले महीने तारीखों का एलान संभव

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग जल्द ही संबंधित राज्यों का दौरा शुरू करेगा। इन दौरों का उद्देश्य चुनाव की तारीखों के एलान से पहले कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारियों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन करना है। माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह के बाद कभी भी चुनावों की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।

इस साल जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। वहीं, तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 10 मई, केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 23 मई, असम की 126 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को पूरा होगा। इसके अलावा, पुडुचेरी की 30 सीटों वाली विधानसभा का कार्यकाल 15 जून 2026 को खत्म हो रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत इन सभी राज्यों में कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई विधानसभा का गठन अनिवार्य है।

सूत्रों के मुताबिक, चूंकि चार राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मई महीने में और पुडुचेरी का जून में समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव आयोग समय से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने में जुट गया है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल सबसे पहले 7 मई को समाप्त हो रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए आयोग की प्राथमिकता भी इसी राज्य पर अधिक रहने की संभावना है।

आयोग फरवरी के अंत से लेकर मार्च के पहले सप्ताह तक इन राज्यों का दौरा कर सकता है। इस दौरान संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के साथ बैठकें की जाएंगी। इसके अलावा, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से भी संवाद किया जाएगा, ताकि चुनाव से जुड़े उनके सुझावों और आपत्तियों को सुना जा सके और यदि कोई वैध बिंदु हो तो उसे चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।

गौरतलब है कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों में तारीखों के एलान से लेकर पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने तक कुल 42 दिन का समय लगा था। बिहार में चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को हुई थी और दो चरणों में मतदान के बाद 16 नवंबर को पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई, जबकि विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक था। इसी पैटर्न को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इन पांच राज्यों में भी चुनावों की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह के बाद की जा सकती है। राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माने जा रहे इन चुनावों को लेकर सभी दलों की निगाहें अब चुनाव आयोग के आधिकारिक एलान पर टिकी हुई हैं।